जम्मू लद्दाख विज़न

आर एन आई नंबर: जेकेएचआईएन/2019/78824 I पोस्टल नंबर : एल-29/जेके.579/24-26

साप्ताहिक I वर्ष : 7 I जम्म I अंक : 12 I सोमवार मार्च 24, 2025 I मूल्य : 3 रूपए I पेज : 16

पटियाला में कर्नल और बेटे के साथ मारपीट मामले में नई एफआईआर, जांच के लिए एसआईटी गठित
पेज 7...

बुधल में हुई मौतों की जांच जारी है-सकीना इत्तू
पेज 12...

बिजबिहाड़ा-श्रीगुफवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में नहरों की वहन क्षमता बढ़ाने के लिए 37.00 करोड़ रूपये की डीपीआर तैयार-जावेद राणा
पेज 14...

आज मुझे गर्व है कि जम्मू-कश्मीर ने फिल्म निर्माण में अपना स्थान पाया है : एलजी सिन्हा

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज अभिनव थिएटर जम्मू में जेएंडके सिने एसोसिएशन द्वारा आयोजित तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में, उपराज्यपाल ने आयोजकों, भाग लेने वाले फिल्म निर्माताओं और स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए समर्पित लघु फिल्म महोत्सव से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी। उपराज्यपाल ने कहा,

ष्सिनेमा शिक्षा का एक प्रभावी माध्यम और सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली एजेंट है। मैं चाहता हूं कि हमारी स्थानीय प्रतिभाएं मनोरंजन और सामाजिक सरोकार के बीच संत.ुलन बनाए रखें और इस शक्तिशाली माध्यम का

उपयोग समाज और सामाजिक परिवर्तन के लाभ के लिए करें।ष उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर में एक जीवंत फिल्म पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रगतिशील फिल्म नीति और अन्य प्रमुख हस्तक्षेपों पर बात की। उपराज्यपाल ने कहा, आज मुझे गर्व है कि जम्मू कश्मीर ने फिल्म निर्माण में अपना स्थान पाया है। पिछले पांच वर्षों में शांति और विकास के हमारे प्रयासों ने जम्मू कश्मीर को हिंदी, क्षेत्रीय और विदेशी फिल्म शूटिंग के लिए और अधिक आकर्षक गंतव्य बना दिया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि तकनीकी प्रगति ने स्थानीय नवोदित फिल्म निर्माताओं, अभिनेताओं और सिनेमा के विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को हमारी समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने में मदद की है। उपराज्यपाल

■ शेष पेज 2...

माता वैष्णो देवी मंदिर में 5 वर्षों में तीर्थयात्रियों के दान में भारी वृद्धि दर्ज की गई

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : मंदिर बोर्ड के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में तीर्थयात्रियों का दान वित्तीय वर्ष 2024-25 (जनवरी तक) में बढ़कर 171.90 करोड़ रुपये हो गया है, जो 2020-21 में 63.85 करोड़ रुपये था। इसी

■ शेष पेज 2...

एएआई ने उधमपुर तक हवाई संपर्क के लिए जमीनी आकलन हेतु पैनल गठित किया

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : उधमपुर जिले में हवाई संपर्क के प्रस्ताव के मद्देनजर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने एक समिति बनाई है जो जमीनी हालात का आकलन करेगी।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, जो कठुआ निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं, ने एक्स पर पोस्ट किया, उधमपुर में हवाई उड़ान उतारने के हमारे प्रस्ताव के अनुसरण में, यह सूचित किया गया है कि सिद्धांत रूप में इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने पोस्ट किया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विमानन क्षेत्र, वायु सेना

के विशेषज्ञों के साथ-साथ पेशेवर पायलटों की एक समिति गठित की है, जो इस प्रस्ताव का आकलन करने और कार्यान्वयन पर काम करने के लिए अगले सप्ताहांत में उधमपुर का दौरा करेगी।

उन्होंने आगे लिखा कि समिति हवाई यातायात, सुरक्षा प्रोटोकॉल, प्रबंधन और अन्य संबंधित पहलुओं का मूल्यांकन करेगी। यह एएआई के अध्यक्ष के कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया है।

इससे पहले अपने पोस्ट में उन्होंने कहा था, ष्हमने हिंडन गाजियाबाद-जम्मू-हिंडन के बीच शुरू की गई नई एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान के लिए रुउधमपुर को हवाई उड़ान स्टॉपओवर के रूप में शामिल करने का महत्वाकांक्षी प्रस्ताव रखा है।ष

हालांकि, इसमें कई मुद्दे शामिल हैं और मंजूरी लेनी होगी, क्योंकि उधमपुर भी जम्मू की तरह ही वायुसेना द्वारा प्रबंधित हवाई अड्डा है, लेकिन

■ शेष पेज 2...

जम्मू-कश्मीर में मुगल रोड के किनारे पर्यटन से संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर सरकार पुंछ और राजौरी को दक्षिण कश्मीर के शोपियां से जोड़ने वाले मुगल रोड के किनारे कई दर्शनीय स्थानों पर पर्यटन से संबंधित बुनियादी

ढांचे को विकसित करने की योजना बना रही है।

पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला ने कहा कि मुगल रोड पर स्थित दुबजान, मुगल सराय, पीर-की-गली और शकरू केलर अपनी प्राकृतिक सुंद.रता और सुंदर परिदृश्य के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें पर्यटन विकास के लिए आशाजनक स्थल बनाते हैं।

■ शेष पेज 2...

सीएस डुल्लू को नई दिल्ली में डायमंड स्टेट्स समिट 2025 में प्रतिष्ठित डायमंड स्टेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर के लिए गर्व की बात यह रही कि मुख्य सचिव अटल डुल्लू को आज न्यूज18 इंडिया द्वारा आयोजित डायमंड स्टेट्स समिट 2025 के ग्रैंड फिनाले में प्रतिष्ठित डायमंड स्टेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।

यह अवार्ड न्यूज18 इंडिया की मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल ने अटल डुल्लू को पिछले कुछ वर्षों में शासन, विकास और प्रगतिशील पहलों में जम्मू-कश्मीर के

■ शेष पेज 2...

शेष पेज १ से.....

आज मुझे गर्व...

ने जम्मू कश्मीर के फिल्म निर्माताओं और कलाकारों से सामा. जिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अपने रचनात्मक प्रयासों के माध्यम से सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

उपराज्यपाल ने कहा, "रचनात्मकता न केवल आपके सपने को पूरा करने का एक स्रोत है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का एक वाहन भी है। मैंने समाज पर विभिन्न रचनात्मक शैलियों का गहरा प्रभाव देखा है लेकिन सिनेमा का प्रभाव अद्वितीय है और उन्होंने कई सामाजिक बुराइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद की है।

मैं चाहता हूं कि हमारे युवा समाज से नशा जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए इस रचनात्मकता का पोषण करें और रचनात्मक प्रतिभाओं का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करें जो दूसरों के जीवन को बदल देंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे युवा वंचितों तक पहुंचने और उनके लिए सम्मान का जीवन सुनिश्चित करने में सरकार की मदद करें "।

इस अवसर पर, उपराज्यपाल ने श्तवी फिल्मोत्सवश का एक ब्रोशर जारी किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के निरंतर प्रयासों के लिए जेएंडके एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर

एंड लैंग्वेज (जेकेएएसीएल) की भी सराहना की। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी, प्रसिद्ध कलाकार, फिल्म निर्माता, जम्मू–कश्मीर सिने एसोसिएशन के सदस्य और विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

माता वैष्णो देवी...

प्रकार, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) ने कहा है कि इसी अवधि के दौरान मंदिर में चढ़ाया गया सोना भी नौ किलोग्राम से बढ़कर 27.7 किलोग्राम हो गया है और चांदी 753 किलोग्राम से बढ़कर 3,424 किलोग्राम हो गई है।

जम्मू स्थित कार्यकर्ता रमन शर्मा द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन का जवाब देते हुए, श्राइन बोर्ड ने कहा कि वित्त वर्ष 2020–21 में दान या भेंट के रूप में 63.85 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, इसके बाद वित्त वर्ष 2021–22 में 166.68 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2022–23 में 223.12 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2023–24 में 231.50 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024–25 (इस साल जनवरी तक) में 171.90 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।

जम्मू–कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर में 2020 में केवल 17.20 लाख तीर्थयात्री आए, जो पिछले तीन दशकों में सबसे कम है। यह मंदिर अपने इतिहास में पहली बार कोविड–19 महामारी के प्रकोप के कारण पांच महीने तक बंद रहा था। इसे 16 अगस्त 2020 को तीर्थयात्रियों के लिए फिर से खोल दिया गया।

1986 में जब तीर्थस्थल बोर्ड ने बेहतर प्रबंधन के लिए तीर्थस्थल के मामलों को अपने हाथ में लिया था, तब से लेकर अब तक तीर्थयात्रियों की संख्या 13.95 लाख थी, जो प्रत्येक बीतते वर्ष के साथ लगातार बढ़ती जा रही है, तथा 2012 में यह संख्या 1.04 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि पिछले वर्ष यह 1.01 करोड़ थी।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2021 में तीर्थयात्रियों का आगमन 55.88 लाख, 2022 में 91.25 लाख, 2023 में 95.22 लाख और 2024 में 94.84 लाख होगा।

तीर्थयात्रियों द्वारा मंदिर में चढ़ाए गए आभूषणों या सोने जैसे आभूषणों के कुल मूल्य के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में, बोर्ड ने कहा कि वित्त वर्ष 2020–21 में 9.075 किलोग्राम सोना प्राप्त हुआ, वित्त वर्ष 2021–22 में 26.351 किलोग्राम, वित्त वर्ष 2022–23 में 33.258 किलोग्राम, वित्त वर्ष 2023–24 में 23.477 किलोग्राम और वित्त वर्ष 2024–25 (इस वर्ष जनवरी तक) में 27.717 किलोग्राम सोना प्राप्त हुआ।

इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2020–21 में 753.630 किलोग्राम, वित्त वर्ष 2021–22 में 2400.705 किलोग्राम, वित्त वर्ष 2022–23 में 3756.582 किलोग्राम, वित्त वर्ष 2023–24 में 4072.486 किला. ग्राम और वित्त वर्ष 2024–25 में इस साल जनवरी तक 3424. 538 किलोग्राम चांदी प्राप्त हुई।

बोर्ड ने कहा कि धातुएं अशुद्ध रूप में प्राप्त हुई हैं और परिष्कृत होने तक उनका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।

इसमें कहा गया है कि सोने जैसी दिखने वाली पीली धातु और चांदी जैसी दिखने वाली सफेद धातु को पिघलाने, परखने, परिष्कृत करने और .995 और .999 शुद्धता के सिक्कों में ढालने के बाद स्मारिका दुकानों पर बिक्री के लिए रखा जाता है।

माता वैष्णो देवी...

उधमपुर में वाणिज्यिक उड़ान उतारने का प्रस्ताव रिकॉर्ड में रखा गया है, अगर हर दिन नहीं तो कम से कम सप्ताह के कुछ दिन/दिनों में। डॉ. सिंह ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारा अनुवर्ती प्रयास सफल होगा।

जम्मू–कश्मीर में...

मुख्यमंत्री ने शनिवार को विधानसभा में निर्दलीय विधायक शब्बीर अहमद कुल्ले के अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

कुल्ले शोपियां निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने वहां अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मुगल रोड के साथ पर्यटन से संबंधित बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों के बारे में जानकारी मांगी है।

उन्होंने कहा कि विभाग ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत 6. 32 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से शोपियां में विभिन्न पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे का विकास किया है। उन्होंने कहा कि कैपेक्स बजट के तहत विभाग ने 2.51 करोड़ रुपये की लागत से 12 कार्य पूरे किए हैं और वित्त वर्ष 2024–25 के लिए 84 लाख रुपये की अनुमानित लागत से आठ नए कार्य शुरू किए गए हैं।

इसके अलावा, विभाग दुबजान और पीर–की–गली में पर्यटन के बुनियादी ढांचे को विकसित करने का इरादा रखता है। हालांकि, वर्तमान में इस क्षेत्र में निर्माण की अनुमति नहीं है, जो वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है, मुख्यमंत्री ने कहा।

हालांकि, उन्होंने कहा कि पीर–की–गली में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए, विभाग ने राज्य कैपेक्स बजट 2024–25 के तहत 35 लाख रुपये की परियोजना लागत पर षहिरपोरा में पीर–की–गली के रास्ते पर कैफेटेरिया और सार्वजनिक सुविधा का निर्माणष का काम शुरू किया है। उक्त सुविधा के निर्माण के लिए भूमि की पहचान और हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा

कि विभाग इन क्षेत्रों में इको–लॉग हट्स, कैफेटेरिया, डॉरमेट्री, व्यूइंग डेक और अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने का भी इरादा रखता है, जिसके लिए विभाग वन विभाग के साथ मामला उठाएगा और परिवेश पोर्टल पर भूमि हस्तांतरण के लिए भी आवेदन करेगा।

सीएस डुल्लू को...

अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए दिया।

इस संबंध में मुख्य सचिव ने इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया और इस पुरस्कार को जम्मू–कश्मीर के लोगों और प्रशासन के सामूहिक प्रयासों को समर्पित किया।

उन्होंने शांति, समृद्धि और विकास के युग की शुरुआत करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर जम्मू–कश्मीर सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने आम जनता के लिए कई अन्य कल्याणकारी उपायों के अलावा लोगों के दरवाजे तक शासन पहुंचाने जैसी विभिन्न पहलों के बारे में बात की।

उन्होंने उन कदमों का भी जिक्र किया, जिनके परिणामस्वरूप जम्मू–कश्मीर में पर्यटकों की आमद बढ़ी है, जो बढ़कर दो करोड़ से अधिक हो गई है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सुरंगों, राजमार्गों, रेलवे और बेहतर हवाई संपर्क जैसे नए संपर्क उपायों को भी श्रेय दिया।

उन्होंने जम्मू–कश्मीर सरकार की विकास, शांति और समृद्धि के एजेंडे को आगे बढ़ाने और अपने नागरिकों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

डायमंड स्टेट्स समिट 2025 में प्रख्यात नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिन्होंने शासन, सामाजिक कल्याण और आर्थिक प्रगति में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस प्रतिष्ठित मंच पर जम्मू–कश्मीर की मान्यता परिवर्तनकारी शासन और विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

उधमपुर : चौपल नाला पुल के धीमे निर्माण से रामनगर के लोग परेशान

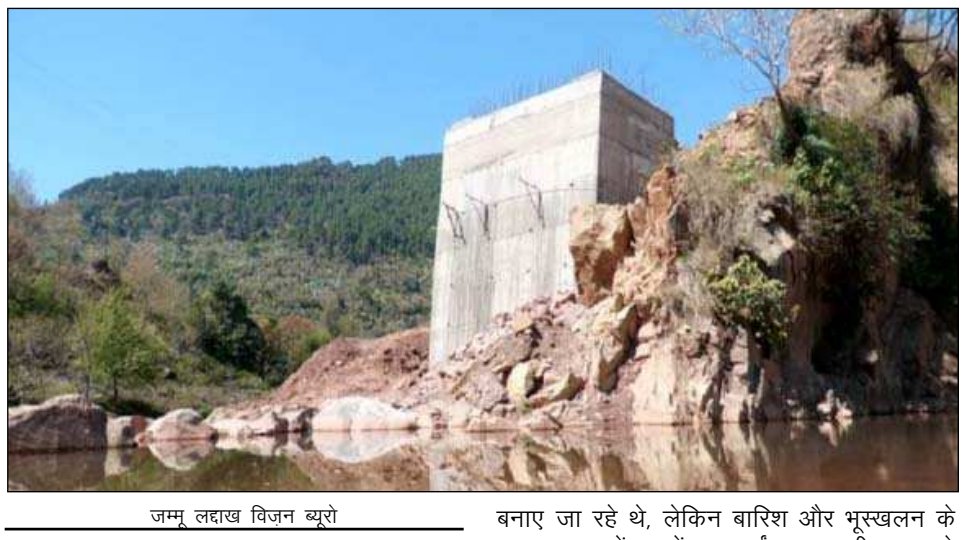

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

उधमपुर : उधमपुर जिले के रामनगर तहसील में चौपल नाले पर एक महत्वपूर्ण पुल का निर्माण धीमी गति से चल रहा है, जिससे 15–20 गांवों में रहने वाले लगभग 70,000–80,000 लोगों को भारी परेशानी हो रही है। दिसंबर 2023 में शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट का काम अभी पूरा होने से बहुत दूर है, जिससे छात्रों को बिना पुल के नाले को पार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और मरीजों और नियमित यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। पीडब्ल्यूडी रामनगर के अधिशासी अभियंता पुरुषोत्तम कुमार जोशी के अनुसार पुल का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। निर्माण के लिए एप्रोच बनाए जा रहे थे, लेकिन बारिश और भूस्खलन के कारण पुल में दरारें आ गईं। साथ ही, पुल के निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री घटिया गुणवत्ता की थी, जिससे निर्माण कार्य का कुछ हिस्सा ध्वस्त हो गया। इंजीनियर जोशी के अनुसार, यह परियोजना नाबार्ड के अंतर्गत आती है और इसे 18 महीने में पूरा किया जाना है।

"मीडिया में वायरल हो रहा पुल अब बनकर तैयार हो चुका है, इसके आधार बन चुके हैं और एप्रोच का काम चल रहा है। एप्रोच का काम जो चल रहा था, बारिश के कारण ध्वस्त हो गया था। हमारे दौरे के समय भी हमने कहा था कि इसे आगे न बढ़ाया जाए, क्योंकि सामग्री अच्छी नहीं थी। इस दौरान बारिश शुरू हो गई, जिससे दीवार में दरारें आ गईं और भूस्खलन में दीवार भी गिर गई। हमने घटिया सामग्री से बनी सारी सामग्री को ध्वस्त कर दिया है और आगे निर्देश हैं कि हम घटिया सामग्री को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यह प्रोजेक्ट नाबार्ड के तहत था और इसे 18 महीने में पूरा किया जाना था। हमने इस पर नोटिस जारी कर दिया है और पुल का काम समय पर पूरा करने को कहा है", पुरुषोत्तम कुमार जोशी ने कहा। नाबार्ड के तहत 2.32 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला 40 मीटर लंबा स्टील गार्डर पुल सुरनी पंचायत को नीली जंदरोर से होते हुए जिला उधमपुर के ब्लॉक मुख्यालय घोरडी से जोड़ेगा। अभी तक केवल आधार का काम हुआ है और एप्रोच का निर्माण कार्य जारी है।

हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, जिससे आधा–अधूरा काम नष्ट हो गया और ब्रेस्ट दीवारों में दरारें पड़ गईं। आधिकारिक निरीक्षण के बाद, ठेकेदार को प्रभावित संरचनाआ. ं को ध्वस्त करने और फिर से काम शुरू करने का निर्देश दिया गया। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर मौजूदा निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है और विभाग के अधिक. ारियों ने ठेकेदार को गुणवत्ता मानकों का पालन करने की चेतावनी जारी की है।

निर्माण में देरी जारी रहने के कारण, पड़ोसी गांवों के हजारों निवासी रोजाना महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं, जिसमें छात्र, मरीज और श्रमिक सबसे ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें खतरनाक रास्ता पार करना पड़ता है।

नार्को-आतंकवाद में शामिल अपराधियों से सख्ती से निपटा जाएगा : डीजीपी

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

पुलवामाः पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात ने शुक्रवार को जम्मू–कश्मीर में नार्को–आतंकवाद में शामिल अपराधियों पर कार्रवाई तेज करने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

दक्षिण कश्मीर में एक जन दरबार को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डीजीपी प्रभात ने कहा, ष्नार्को–आतंकवाद में शामिल अपराधियों से सख्ती से निपटा जाएगा। डीजीपी ने इस बात पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि क्या आने वाले दिनों में घुसपैठ बढ़ने की कोई संभावना है क्योंकि बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ष्मौसम विभाग की तरह भविष्यवाणियां न करें। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और भी जन दरबार आयोजित किए जाएंगे।

सकीना इटू ने अनंतनाग के कादीपोरा में आग प्रभावित परिवारों से मुलाकात की

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

अनंतनाग : स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण एवं शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने कल हुई विनाशकारी आग की घटना से प्रभावित परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए आज कादीपोरा, अनंतनाग का दौरा किया।

विधायक पीरजादा मोहम्मद सईद, अब्दुल मजीद लारमी और अल्ताफ अहमद वानी, डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद और जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मंत्री के साथ थे।

यात्रा के दौरान, सकीना ने व्यक्तिगत रूप से पीड़ितों से बातचीत की, उनकी शिकायतों का आकलन किया और चल रहे राहत उपायों का जायजा लिया। इस अवसर पर प्रभावित परिवारा. ं से बातचीत करते हुए, मंत्री ने उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वा. सन दिया। सकीना ने कहा, ष्मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के निर्देश पर, विधायकों की मेरी टीम आपके साथ एकजुटता में खड़ी है। हमारी सरकार आपको इस दुखद नुकसान से उबरने के लिए हर संभव सहायता और सहायता प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रही हैं और इस विनाशकारी आग की घटना के बारे में जमीनी स्तर पर जानकारी जुटाने के लिए कल रात से ही जिला प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहा, ष्आग से प्रभावित परिवारों को जो दुखद क्षति हुई है, वह दिल दहला देने वाली है और इसकी भरपाई शब्दों में नहीं की जा सकती। लेकिन हमारी सरकार इस संकट की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी आवश्यक सहायता और समर्थन बिना किसी देरी के आप तक पहुंचे।ष

मंत्री ने उपायुक्त से पुनर्वास प्रक्रिया में तेजी लाने का भी आग्रह किया। उन्होंने पीड़ितों को अपना जीवन फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए अस्थायी आश्रय, खाद्य आपूर्ति और वित्तीय सहायता सहित तत्काल राहत की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने जिला प्रशासन से नुकसान का गहन आकलन करने और प्रभावित परिवारों को शीघ्र मुआवजा देने का भी आह्वान किया।

स्थानीय निवासियों और अग्नि पीड़ितों की भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निवारक उपायों की आवश्यकता के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए, सकीना इटू ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार इस इलाके में भीड़भाड़ को कम करने की संभावना तलाशेगी और इलाके में अग्नि सुरक्षा बुनियादी ढांचे को भी बढ़ाया जाएगा।

बाद में, मंत्री ने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिका. रियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की और राहत के साथ–साथ तत्काल पुनर्वास उपायों का विस्तृत मूल्यांकन किया।

बैठक के दौरान, मंत्री ने उपायुक्त को इन अग्नि प्रभावित परिवारों के लिए अस्थायी आश्रय सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जिला प्रशासन से इन पीड़ितों के लिए उपयुक्त बिस्तर और अन्य आवश्यक चीजों की व्यवस्था करने को कहा।

मंत्री ने प्रभावित परिवारों को तत्काल आधार पर लकड़ी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए ताकि उन्हें जीवनयापन करने में सहायता मिल सके। सकीना ने अधिकारियों से किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए एक मेडिकल टीम उपलब्ध रखने को कहा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से दवाओं और अन्य आवश्यक उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रखने को भी कहा।

मंत्री ने जिला प्रशासन से नुकसान का तत्काल आकलन करने और प्रभावित परिवारों को उचित सहायता के लिए त्वरित व्यवस्था करने को कहा। गौरतलब है कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के भीड़भाड़ वाले पुराने शहर कादीपोरा में एक भीषण आग की घटना में 30 से अधिक घर जलकर खाक हो गए, जिससे करीब 45 परिवार प्रभावित हुए।

चिट्टीसिंहपोरा नरसंहार पर जल्द बनेगी फिल्मः लेखक–निर्देशक राजेश राजा ने की घोषणा

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

चिट्टीसिंहपोरा (श्रीनगर), 21 मार्च : कश्मीर के चिट्टीसिंहपोरा में 35 सिखों के नरसंहार पर आधारित फिल्म का निर्माण जल्द शुरू होगा। इस बात की घोषणा फिल्म के लेखक एवं निर्देशक राजेश राजा ने 21 मार्च 2025 को गुरुद्वारा चिट्टीसिंहपोरा में आयोजित शहीदे–ए–खालसा समागम के दौरान की।

20 मार्च को शहीदों की याद में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुआ. ं ने भाग लिया। अगले दिन, 21 मार्च को समागम की भोग रसम दोपहर 2 बजे संपन्न हुई। श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में मत्था टेककर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

समारोह में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव सरदार इचपाल सिंह ने सभी श्रद्धालुओं का धन्यवाद करते हुए कहा कि शहीदों के बलिदान को दुनिया तक पहुंचाने के लिए यह फिल्म एक महत्वपूर्ण पहल होगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही फिल्म का निर्माण कार्य शुरू होगा, जिससे इस दर्दनाक त्रासदी की सच्चाई दुनियाभर के सामने आ सकेगी।

निर्देशक राजेश राजा ने कहा कि यह फिल्म शहीदों की याद में एक ऐतिहासिक दस्तावेज बनेगी, जो उनकी शहादत को हमेशा के लिए अमर कर देगी।

उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग शीघ्र ही शुरू होगी और इसे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा।

सरकार जम्मू–कश्मीर में 1600 नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने पर विचार कर रही हैः सतीश शर्मा

राशन कार्ड में नियमित आधार पर छूटे हुए परिवार के सदस्यों को जोड़ा जा रहा हैरू खाद्य मंत्री

जम्मू–कश्मीर में पीएम राशन योजना के तहत 98.52 लाख एएवाई, पीएचएच, एनपीएचएच लाभार्थी शामिल, चेनानी निर्वाचन क्षेत्र में 56.977

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सतीश शर्मा ने आज कहा कि विभाग जम्मू –कश्मीर में 1600 नई उचित मूल्य दुकानें खोलने पर विचार कर रहा है।

मंत्री विजय कुमार द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। मंत्री ने सदन को सूचित किया कि सरकार जम्मू–कश्मीर में नई उचित मूल्य की दुकानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्वाचित सदस्यों को शामिल करने के लिए विवेकपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जम्मू–कश्मीर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक संशोधन किए जाने के बाद आगे कदम उठाए जाएंगे।

इस बीच, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री सतीश शर्मा ने आज कहा कि जम्मू–कश्मीर में राशन कार्ड में पात्र छूटे हुए परिवार के सदस्यों को जोड़ने का काम नियमित आधार पर किया जा रहा है।

मंत्री बलवंत सिंह मनकोटिया द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

मंत्री ने कहा कि जम्मू–कश्मीर में पीएम राशन योजना के तहत 98.52 लाख एएवाई, पीएचएच और एनपीएचएच लाभार्थियों को कवर किया गया है, जबकि चेनानी निर्वाचन क्षेत्र में 56,977 लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि विभाग प्रचलित ढांचे के अनुसार नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने पर विचार कर रहा है, जो जम्मू–कश्मीर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हिस्सा है।

मंत्री ने कहा कि चूंकि निर्वाचित सरकार ने कार्यभार संभाला है, इसलिए जम्मू–कश्मीर में नई उचित मूल्य की दुकानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्वाचित सदस्यों को शामिल करना उचित समझा गया है, जिसके लिए मौजूदा ढांचे पर फिर से विचार करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, विशेष रूप से एएवाई परिवारों के तहत परिवारों को कवरेज के लिए निर्धारित लक्ष्यों का पालन करने के लिए राशन कार्डों का विभाजन रोक दिया गया है, जहां पात्रता 35 किलोग्राम प्रति परिवार के पैमाने पर है।

मंत्री ने कहा कि नए राशन कार्ड जारी करने के माध्यम से राशन कार्डों को विभाजित करने की प्रक्रिया से ऐसे नए परिवारों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि इससे खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं और सरकार की अन्य योजनाओं के तहत विभाग पर बोझ बढ़ने के निहितार्थ भी हैं, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली डेटाबेस का उपयोग किया जाता है और पात्रता की इकाई घर है। हालांकि, पात्र छूटे हुए परिवार के सदस्यों को उनके घरेलू राशन कार्ड में नियमित आधार पर जोड़ा जा रहा है।

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा को तलाक की मंजूरी मिल गई है

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

मुंबई : यहां की एक पारिवारिक अदालत ने गुरुवार को क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी अलग रह रही पत्नी द्वारा आपसी सहमति से तलाक की मांग वाली संयुक्त याचिका को स्वीकार कर लिया। अलग रह रहे दंपति बांद्रा स्थित पारिवारिक अदालत में पेश हुए।

चहल के वकील नितिन गुप्ता ने कहा कि पारिवारिक अदालत ने चहल और वर्मा द्वारा आपसी सहमति से तलाक के लिए दायर संयुक्त याचिका पर फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि पक्षों ने सहमति की शर्तों का पालन किया है।

गुप्ता ने कहा, ष्पारिवारिक अदालत ने चहल और वर्मा द्वारा आपसी सहमति से तलाक की मांग वाली संयुक्त याचिका को स्वीकार कर लिया है।

चहल और वर्मा की शादी दिसंबर 2020 में हुई थी। उनकी याचिका के अनुसार, वे जून 2022 में अलग हो गए।

5 फरवरी को उन्होंने आपसी सहमति से तलाक की मांग करते हुए पारिवारिक अदालत में एक संयुक्त याचिका दायर की।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को पारिवारिक अदालत से गुरुवार तक तलाक की याचिका पर फैसला करने का अनुरोध किया, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि चहल बाद में उपलब्ध नहीं होंगे क्योंकि वह आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। आईपीएल टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट 22 मार्च से शुरू होने वाला है।

चहल पंजाब किंग्स टीम का हिस्सा हैं। हाईकोर्ट ने बुधवार को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की याचिका दायर करने के बाद प्रत्येक जोड़े के लिए निर्धारित छह महीने की कूलिंग पीरियड को भी माफ कर दिया। क्रिकेटर और वर्मा ने हाईकोर्ट के समक्ष एक संयुक्त याचिका दायर की थी, जिसमें मांग की गई थी कि उनके मामले में कूलिंग पीरियड को माफ किया जाए क्योंकि उन्होंने आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन किया है।

पीडीपी विधायक से कटौती प्रस्तावों को अस्वीकार करने संबंधी टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा गया

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : जम्मू –कश्मीर विधानसभा में बुधवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायक वहीदुर्रहमान पर्रा के इस आरोप पर हंगामा हुआ कि अनुदानों में उनके कटौती प्रस्तावों को मिटा दिया गया।जम्मू यात्रा गाइड

कथित शिकायत के कारण स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने जनता और मीडिया को गुमराह करने के आरोप में उनसे माफ़ी मांगी। स्पीकर ने कहा कि सदन का कामकाज विधानसभा के नियम 227 के अनुसार चलता है, जिसके अनुसार विधायकों को अनुदान पेश किए जाने से तीन दिन पहले कटौती प्रस्ताव पेश करना होता है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि सदस्यों के कटौती प्रस्ताव अनुदान पेश किए जाने से एक दिन पहले ही प्राप्त हुए थे।

प्रश्नकाल समाप्त होने पर स्पीकर ने पार्रा की एक्स पर पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें पीडीपी विधायक ने दावा किया था कि उन्हें कटौती प्रस्ताव पेश करने की अनुम. ति नहीं थी और उन्हें अनुदान में शामिल नहीं किया गया था। स्पीकर ने कहा, आप एक शिक्षित सदस्य हैं और आपने (एक्स पर) अपनी टिप्पणियों से जनता और मीडिया की राय को प्रभावित करने की कोशिश की। आपने उन्हें गुमराह करने का प्रयास किया। आपको जनता की राय को गुमराह नहीं करना चाहिए था।ष उन्होंने कहा कि विधानसभा चर्चा के लिए सर्वोच्च मंच है और पार्रा को अपनी टिप्पणियों के लिए माफ़ी मांग. नी चाहिए। हालांकि, पार्रा ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने पहले की अनुदान प्रस्तुतियों में इस्तेमाल किए गए पैटर्न के अनुसार ही अपने कटौती प्रस्ताव पेश किए थे। ष्उन्हें तब शामिल किया गया था। जल्द ही नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के कई सदस्यों और एक निर्दलीय विधायक ने उनका सामना किया, जिससे विधानसभा में कुछ देर के लिए हंगामा हुआ।

इसके बाद स्पीकर ने सत्ता पक्ष के सदस्यों और निर्दलीय विधायक मेहराज मलिक को संबोधित किया और उन्हें शांत रहने और अपनी बेंच पर बैठने को कहा। स्पीकर ने कहा, "नियमों के अनुसार, सदन में अनुदान पेश किए जाने से तीन दिन पहले कटौती प्रस्ताव पेश किए जाने चाहिए। हालांकि, आपने एक दिन पहले रात 11.37 बजे ईमेल के जरिए अपने कटौती प्रस्ताव पेश किए। कटौती प्रस्तावों को संकलित करके संबंधित विभागों को प्रतिक्रिया के लिए भेजा जाना चाहिए, जिसमें समय लगता है। इतने कम समय में उन्हें कैसे स्वीकार किया जा सकता है? आपको नियमों के बारे में पता होना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि पारा द्वारा पेश किए गए 105 कटौती प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं।

जब पारा ने दावा किया कि उन्हें बताया गया था कि उनके कटौती प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे, तो स्पीकर और एनसी सदस्य ने मांग की कि वह उस अधिकारी का नाम बताएं जिसने उन्हें यह बताया।

स्पीकर ने टिप्पणी की, "आपको जिम्मेदार होने की जरूरत है। मैं इस मुद्दे को बंद करना चाहता हूं।" पारा ने आरोप लगाया कि चल रहे बजट सत्र के दौरान कटौती प्रस्तावों में उनके सवालों को जानबूझकर मिटा दिया गया।

मंगलवार को, जब बजट सत्र चल रहा था, पर्रा ने एक्स को लिखा कि जम्मू–कश्मीर सरकार 5 अगस्त के कदम की पुष्टि के लिए राज्यपाल शासन का विस्तार मात्र है।

"यह एक निजी मामला है": विधायक मेहराज मलिक ने गैर-जमानती वारंट पर प्रतिक्रिया दी

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : आप विधायक मेहराज मलिक ने जम्मू की एक अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर–जमानती वारंट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह एक निजी मामला है और वह विधानसभा में अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मलिक ने कहा,

मैं एक विधायक हूं; आप मुझसे पूछ सकते हैं कि विधानसभा में क्या चल रहा है। यह (गैर–जमानती वारंट) एक निजी मामला है। आप इसके अलावा किसी और चीज के बारे में पूछ सकते हैं... मैं उस मामले पर बोलना नहीं चाहता; लोग इसे देखेंगे। उन्होंने आगे कहा, जिन्होंने मुझे राजनीति सिखाई, वे अब मुझे कानून भी सिखाएंगे... मुझे नहीं पता कि वारंट क्या है। मैं लोगों के मुद्दों के साथ विधानसभा में व्यस्त हूं... यह एक गैर–जमानती वारंट है। मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है और जमानत मिल सकती है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मैंने किसी को नहीं मारा है...

मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने जम्मू-कश्मीर के लिए जीआईएस आधारित भूमि बैंक बनाने का अनुरोध किया

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दी गई वन भूमि के बदले प्रतिपूरक वनीकरण की सुविधा के अलावा विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए भूमि बैंक बनाने हेतु भूमि पार्सल की पहचान की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्य सचिव ने दोनों संभागीय और जिला प्रशासनों को अपने अधिकार क्षेत्र में सभी सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पार्सल की पहचान करने का निर्देश दिया। उन्होंने भूमि पहचान के लिए एक व्यापक और व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसी सभी भूमि विकास उद्देश्यों और अन्य सामाजिक–आर्थिक कल्याण उपायों के लिए उनकी उपयुक्तता के

आधार पर ठीक से वर्गीकृत की गई हैं। पहचान प्रक्रिया में सटीकता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, मुख्य सचिव ने वन विभाग को राजस्व विभाग के समन्वय में पहचाने गए भूमि पार्सल की जीआईएस मैपिंग करने का निर्देश दिया।

भूमि वर्गीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि भूमि बैंकों को उन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए जो बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उपयुक्त हैं और जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार केवल वनीकरण के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।

वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण आयुक्त सचिव शीतल नंदा ने बैठक में बताया कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जो प्रतिपूरक वनीकरण के लिए उपयुक्त गैर–वन भूमि की पहचान करने और भूमि बैंक बनाने के लिए है।

उन्होंने बताया कि यह पहल वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अनुरूप है, जो यह सुनिश्चित करता है कि गैर–वन उद्देश्यों के लिए दी गई वन भूमि के बदले में वनीकरण हो। उन्होंने दोहराया कि यह उपाय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में है कि पर्याप्त प्रतिपूरक वनीकरण के बिना वन भूमि में कोई शुद्ध कमी नहीं होनी चाहिए।

प्रगति पर अद्यतन जानकारी देते हुए, पीसीसीएफ (एचओएफएफ), सुरेश कुमार गुप्ता ने बैठक में बताया कि प्रतिपूरक वनरोपण के लिए जम्मू–कश्मीर में 553,263 कनाल में फैले 2,576 भूमि खंडों की पहचान की गई है। राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण के बाद, 14,797 कनाल और 154 मरला के 82 खंड अतिक्रमण से मुक्त पाए गए और वनरोपण के लिए भूमि बैंक में शामिल किए जाने के लिए उपयुक्त पाए गए।

एनएचएम कर्मचारियों का वेतन 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 15 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक संशोधित किया गया : सकीना इटू

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने आज सदन को बताया कि वर्ष 2021–22 के दौरान जम्मू–कश्मीर में सभी एनएचएम कर्मचारियों का वेतन 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसमें सालाना 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। मंत्री ने सदन को बताया कि जम्मू –कश्मीर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, "जम्मू–कश्मीर में एनएचएम कर्मचारियों के लिए वेतन समायोजन, विशेष रूप से अन्य राज्यों के कर्मचारियों के बराबर वेतन अंतर को पाटने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुरूप होना चाहिए। इसलिए, एनएचएम के उद्देश्यों और बजट आवंटन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे परिवर्तनों के लिए केंद्रीय मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।"

मंत्री विधानसभा में चौधरी विक्रम रंधावा द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। के लिए एनएचएम के उद्देश्यों और बजट आवंटन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है", उन्होंने कहा। चिकित्सा अधिकारी (एमबीबीएस) के लिए वेतन 30,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये किया गया है, साथ ही 15,000 रुपये का विशेष प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन भी दिया गया है; चिकित्सा अधिकारी (आयुष) के लिए वेतन 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये किया गया है और दंत चिकित्सकों के लिए वेतन 23,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये प्रति माह किया गया है। रणबीर सिंह पठानिया और डॉ. रामेश्वर सिंह द्वारा उठाए गए पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार नियमितीकरण के साथ–साथ वेतन वृद्धि का मुद्दा भारत सरकार के समक्ष उठाएगी।

उच्च स्तरीय समिति ने कटरा के हितधारकों के साथ 5वीं परामर्श बैठक आयोजित की

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

कटरा : उपराज्यपाल, जेके–यूटी तथा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) के अध्यक्ष द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने विधायक, श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र, कटरा; विधायक रियासी, अध्यक्ष डीडीसी, रियासी; मुस्कान चौरिटेबल ट्रस्ट, कटरा और बाणगंगा–चरणपादुका शॉप्स एसोसिएशन सहित विभिन्न संघों और समूहों के प्रति. निधियों के साथ अपनी पांचव. ीं महत्वपूर्ण बैठक की।

यह बैठक विभिन्न संगठनों और समूहों के अनुरोधों के प्रत्युत्तर में शीघ्र बुलाई गई थी, जिससे सामुदायिक सहभागिता के प्रति समिति के सक्रिय दृष्टिकोण तथा रोपवे परियोजना पर स्थानीय लोगा. ं से सुझाव प्राप्त करने की प्रतिबद्धता का पता चला।

डॉ. अशोक भान की अध्यक्षता वाली समिति में एसएमवीडीएसबी के सदस्य सुरेश शर्मा, जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और एसएमवीडीएसबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग शामिल थे।

समिति ने एसोसिएशनों और समूहों के साथ चर्चा की, जिसका ध्यान हितधारकों की चिंताओं को दूर करने और उनसे फीडबैक एकत्र करने पर केंद्रित था।

कश्मीर में 35 सिखों के नरसंहार पर बनेगी फिल्म, राजेश राजा ने महंत मंजीत सिंह जी से की मुलाकात

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

प्रसिद्ध लेखक एवं निर्देशक राजेश राजा ने 16 मार्च को महंत साहिब श्री मंजीत सिंह जी (मुख्य संरक्षक, नंगाली साहिब, पुंछ, जम्मू–कश्मीर) से भेंट कर कश्मीर में 35 सिखों के नरसंहार (20 मार्च 2000) पर आधारित अपनी आगामी फिल्म को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य फिल्म की पटकथा में वर्णित ऐतिहासिक तथ्यों की समीक्षा करना, इस संवेदनशील विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त करना एवं सिख समुदाय के दृष्टिकोण को समझना था। बैठक के दौरान, कश्मीर में सिख इतिहास को सिनेमा के माध्यम से प्रस्तुत करने की संभावनाओं पर भी विस्तार से विचार–विमर्श किया गया।

राजेश राजा ने महंत मंजीत सिंह जी को फिल्म की कहानी और पटकथा से अवगत कराया तथा इस ऐतिहासिक घटना पर केंद्रित अपनी शोध और प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह फिल्म न केवल सिख समुदाय के बलिदानों और संघर्षों को प्रदर्शित करेगी, बल्कि इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को दुनिया के सामने लाने का प्रयास भी करेगी।

बैठक में फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति और अन्य आवश्यकताओं पर भी चर्चा की गई।

महंत मंजीत सिंह जी ने विषय की गंभीरता को समझते हुए इस पर गहरी रुचि व्यक्त की और निर्देशक को अपने मार्गदर्शन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐतिहा. सिक घटनाओं को सच्चाई और संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने अतीत से परिचित हो सकें।

इस अवसर पर पुरुषोत्तम गुप्ता, मंजीत सिंह, पुरुषोत्तम मनहास सहित कई सहयोगी सदस्य भी उपस्थित रहे। यह फिल्म सिख समुदाय की पीड़ा, संघर्ष और बलिदान को सिनेमा के माध्यम से जीवंत करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास होगी।

मोदी की कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के दरवाजे तक ले जाएं : सत

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : जम्मू–कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा सीए ने पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के दरवाजे तक ले जाने का आग्रह किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी लाभ उठा सके।

वह जम्मू उत्तर जिले के अंतर्गत आने वाले जानीपुर मंडल की बैठक में बोल रहे थे।

बैठक में जिला अध्यक्ष नंद किशोर, जानीपुर मंडल अध्यक्ष साहिल गुप्ता ने भी विचार रखे।

वरिष्ठ नेता प्रदुमन सिंह, रवीश मेंगी, सुबाष शर्मा, पूर्व. पार्षद सुनीता गुप्ता, पूर्व. इस अवसर पर पार्षद अजय मन्हास, संजय भट्ट, अशोक शर्मा, संकेत शर्मा, राकेश गुप्ता, नारायण दास, सुभाष शर्मा, विशाल गंडोत्रा और विजय वर्मा भी उपस्थित थे।

सत शर्मा सीए ने केंद्र सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने समाज के गरीब, हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से स्वास्थ्य सेवा, आवास, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता और सामा. जिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करके सरकार और लोगों के बीच सेतु का काम करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, जन धन योजना और मुद्रा योजना जैसी कई परिवर्तनकारी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं।

यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि कोई भी पात्र लाभार्थी छूट न जाए और लोग बिना किसी बाधा के लाभ प्राप्त कर सकें।

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अपने–अपने क्षेत्रों में घर–घर जाएं, नागरिकों को विभिन्न कल्याणकारी पहलों के बारे में शिक्षित करें और लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने में उनकी मदद करें।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जमीनी स्तर पर इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से भाजपा की गरीब–हितैषी नीतियों में लोगा. का विश्वास और मजबूत होगा और एक मजबूत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मदद मिलेगी।

शर्मा ने आगे दोहराया कि भाजपा ष्सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वासष के लिए समर्पित है और प्रत्येक पार्टी कार्यकर्ता को विक. सित और समृद्ध भारत के सपने को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

अरविंद ने कहा, मेरी प्राथमिकता जम्मू पश्चिम के लोगों के लिए बेहतर नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करना है

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : वरिष्ठ भाजपा नेता और जम्मू पश्चिम के विधायक अरविंद गुप्ता ने आज भारत नगर, वार्ड नंबर 40 में मैकडैमाइजेशन और ब्लैकटॉपिंग कार्य की शुरुआत की, जिसमें कबीर कॉलोनी और विजय नगर सहित इसके संबद्ध लिंक शामिल हैं, जिसकी अनुमानित लागत 22 लाख रुपये है। यह पहल व्यापक बुनियादी ढांचा विकास योजना का हिस्सा है जिसका उद्देश्य सड़क संपर्क में सुधार करना और जम्मू पश्चिम के निवासियों के लिए बेहतर नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करना है।

इस अवसर पर बोलते हुए, वरिष्ठ भाजपा नेता ने जोर देकर कहा कि कई विकास परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं और निर्वाचन क्षेत्र में समग्र बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि जम्मू पश्चिम का कोई भी क्षेत्र विकास के मामले में पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार जनता की शिकायतों को दूर करने और लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, ष्मोदी सरकार ने हमेशा नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है।

हमारी सरकार हर वार्ड में गुणवत्तापूर्ण सड़कें, आधुनिक सुविधाएं और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। उन्होंने लोगों से फीडबैक देकर और तत्काल ध्यान देने की जरूरत वाले स्थानीय मुद्दों को उजागर करके विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया।

विधायक अरविंद ने दो. हराया कि विकास की गति जारी रहेगी और आश्वासन दिया कि आने वाले महीनों में हर वार्ड में महत्वपूर्ण सुधार होंगे।

इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल अंगराल, जेई शादाब, पूर्व पार्षद चमन लाल भगत, पूर्व पार्षद नीलम नरगोत्रा और सतपाल, विकास कुमार, सोनाली गुप्ता, अरुण दुबे और नरेश गुप्ता सहित कई प्रमुख भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।

स्थानीय लोगों ने बेहतर सड़कों की उनकी लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए विधायक अरविंद गुप्ता और प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने जम्मू पश्चिम को एक आदर्श निर्वाचन क्षेत्र में बदलने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की।

सरकार वंचितों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध–सकीना इत्तू

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : समाज कल्याण, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने कहा कि सरकार जम्मू–कश्मीर की वंचित आबादी के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने निजामुद्दीन भट्ट द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बात कही। उन्होंने सदन को बताया कि समाज कल्याण विभाग व्यापक योजनाओं और पहलों के माध्यम से बांदीपोरा जिले सहित जम्मू–कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में गरीब, विकलांग, वृद्ध और बीमार आबादी के उत्थान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा वंचितों के कल्याण के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का लाभ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा/तलाक पेंशन योजना, विकलांगता पेंशन योजना, ट्रांसजेंडर पेंशन योजना, राज्य विवाह सहायता योजना, लाडली बेटी, पीएमएमवीवाई और अन्य विभिन्न कल्याणकारी और प्रमुख पहलों में शामिल हैं। मंत्री ने विधायकों से अंतिम लाभार्थियों के अधिकतम कवरेज के लिए पात्रता, मानदंड और ऑनलाइन आवे. दन प्रक्रिया के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का आग्रह किया। गुरेज जैसे दूरद. राज के इलाकों में लाभार्थियों की सुविधा के लिए, मंत्री ने आश्वासन दिया कि मेडिकल बोर्ड के रूप में गठित डॉक्टरों की एक टीम इन क्षेत्रों में एक निश्चित दिन शिविर आयोजित करेगी ताकि उन्हें विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए आवश्यक पात्रता कवरेज की सुविधा मिल सके।

जम्मू–कश्मीर में एमओ के करीब 550 पद खाली : जावेद डार

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

बारामूला में शीरी, क्रेरी ब्लॉकों में 57 स्वास्थ्य संस्थान कार्यरत हैं

जम्मू : "जम्मू और कश्मीर में चिकित्सा अधिक. ारियों (एमओ) के लगभग 550 पद रिक्त हैं और 181 एमओ का चयन प्रक्रिया में है", कृषि उत्पादन विभाग के मंत्री जावेद अहमद डार ने विधानसभा में डॉ. सज्जाद शफी और जावेद हसन बेग द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री की ओर से जवाब देते हुए कहा।

मंत्री ने बताया कि बारामूला जिले के शीरी और क्रेरी ब्लॉक में 57 स्वास्थ्य संस्थान कार्यात्मक हैं।

ब्लॉक क्रेरी में चिकित्सा अधिकारियों और पैरामेडिक्स सहित स्वीकृत स्टाफ 157 हैं, 121 कार्यरत हैं जबकि 36 रिक्त हैं। इसी तरह, ब्लॉक शीरी में स्वीकृत स्टाफ 330 है, 223 कार्यरत हैं और 107 रिक्त हैं।

इन पदों में नियमित श्रेणी और एनएचएम शामिल हैं, उन्होंने कहा

कि मंत्री ने कहा कि सीएचसी चंदूसा के संबंध में भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है वर्ष 2021–2022 के दौरान एनटीपीएचसी लारिडोरा की भूमि मुआवजे के लिए 8 लाख रुपये जारी किए गए हैं, जिसे जिला विकास आयुक्त, बारामुल्ला के निपटान में रखा गया है। वित्तीय वर्ष बंद होने के कारण उक्त राशि का भुगतान भूमि मालिक को नहीं किया जा सका और धन. राशि लैप्स हो गई।

हालांकि, उक्त भूमि पर एनटीपीएचसी का निर्माण पूरा हो चुका है और वर्तमान में एनटीपीएचसी लारिडोरा सितंबर 2024 से इस नवनिर्मित भवन से कार्य कर रहा है।

मंत्री ने सदन को सूचित किया कि विभाग चिकित्सा अधिकारियों की रिक्तियों के चल रहे मुद्दे को हल करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, जो वर्तमान में लगभग 550 पद हैं। उन्होंने कहा कि जेकेपीएससी के साथ 181 चिकित्सा अधिकारी पदों के लिए चयन प्रक्रिया अभी भी चल रही है और एक बार चयन पूरा हो जाने के बाद, उन्हें गंभीर स्टाफ की कमी का सामना कर रहे स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात किया जाएगा।

मंत्री ने सदन को आगे बताया कि विभाग 91 चयनित चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रतीक्षा सूची संचालित करने की प्रक्रिया में भी है, जिन्हें स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए जम्मू और कश्मीर में कम सेवा वाले क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा।

बारामुल्ला जिले में चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों के बारे में मंत्री ने सदन को बताया कि जिले के विभिन्न चिकित्सा ब्लॉकों में स्वीकृ त 275 चिकित्सा अधिकारियों में से 219 पद पर हैं और 56 पद रिक्त हैं।

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की ओर दिया जा रहा है विशेष ध्यान

भारत में, नागरिकों की दिनचर्या में आ रही गिरावट एवं खानपान में आए बदलाव के चलते देश में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसका इलाज महंगा होने के कारण आम नागरिकों के लिए इस बीमारी का इलाज कराना बहुत मुश्किल कार्य होता जा रहा है।

प्रह्लाद सबनानी

प्राचीनकाल में भारत के नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति चेतना का भाव जागृत रहता था। जागरूकता तो यहां तक थी कि किस प्रकार जीवन की दिनचर्या स्थापित हो कि परिवार में कोई बीमार ही नहीं हो, बीमारी का निदान तो आगे की प्रक्रिया रहती है। उस खंडकाल में प्रत्येक नागरिक इतना सजग रहता था कि प्रातःकाल एवं सायंकाल में 5/10 किलोमीटर तक नियमित रूप से पैदल चलना एवं योगक्रिया तथा प्राणायाम आदि का अभ्यास नियमित रूप से करता था ताकि शरीर को किसी भी प्रकार का रोग ही नहीं लगे एवं शरीर स्वस्थ बना रहे। इसके साथ ही खानपान, सामान्य दिनचर्या, सूरज डूबने के पूर्व भोजन करना, रात्रि में जल्दी सोना और प्रातःकाल में जल्दी उठना, दिन भर मेहनत के कार्य करना, जैसी प्रक्रिया सामान्यजन की हुआ करती थी। परंतु, आज परिस्थितियां बदली हुई सी दिखाई देती हैं। पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे रुझान के चलते युवाओं के खानपान में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देता है, दिनचर्या में परिवर्तन दिखाई देता है, रात्रि में बहुत देर से सोना और सूर्य नारायण के उदित होने के पश्चात दिन में बहुत देर से उठना आदि कारणों के चलते विभिन्न प्रकार की बीमारियां नागरिकों को घेरने लगी हैं। अतः केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अपने बजट में विशेष प्रावधान करने पड़ रहे हैं। आज, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा यह प्रयास किए जा रहे हैं कि समाज के हर वर्ग तक सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से पहुंचें और आज सरकार की यह प्राथमिकता बन गई है। देश में नागरिकों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 175,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। इन सभी प्रयासों के चलते आज भारत में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी व्यापक कमी दृष्टिगोचर हुई है और केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के चलते एवं अस्पताल, इलाज और दवा की व्यवस्था के कारण एक सामान्य परिवार में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च निरंतर कम हो रहा है।

भारत में, नागरिकों की दिनचर्या में आ रही गिरावट एवं खानपान में आए बदलाव के चलते देश में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसका इलाज महंगा होने के कारण आम नागरिकों के लिए इस बीमारी का इलाज कराना बहुत मुश्किल कार्य होता जा रहा है। अतः केंद्र सरकार ने कैंसर दवाओं के आयात पर कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा, अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए, सर्वाइकल कैंसर के लिए अब तक लगभग नौ करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। देश में लगातार बढ़ रही कैंसर के मरीजों की संख्या को देखते हुए देश के समस्त जिलों में आगामी 3 वर्षों के दौरान डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना कर दी जाएगी। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान 200 डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना की जा रही है।

इसी प्रकार केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से दिमागी बुखार से लड़ने में देश को बहुत सफलता मिली है। इससे होने वाली मृत्यु दर अब घटकर छह प्रतिशत रह गयी है। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी के मरीजों की संख्या भी घटी है। भारत को टीबी मुक्त बनाए जाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम की सही ट्रैकिंग रखने के लिए न—ॅप्छ नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर अब तक लगभग तीस करोड़ वैक्सीन खुराक दर्ज हो चुकी है। टेली मेडिसिन के माध्यम से तीस करोड़ से अधिक ईदृटेली—कन्सल्टेशन से नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ मिला है।

देश में यदि विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं तो इन बीमारियों के पहचानने के लिए उचित संख्या में डॉक्टरों की उपलब्धता बनी रहे एवं विशेष रूप से गांवों में भी डॉक्टर उपलब्ध रहें इस हेतु केंद्र सरकार द्वारा देश में डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाने के लिए पिछले 10 वर्षों के दौरान देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 110,000 नई मेडिकल सीटों का सृजन, 130 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ, किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटों का सृजन भी किया जा रहा है ताकि आगामी पांच वर्षों के दौरान देश के मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटों के सृजन के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। साथ ही, केंद्र सरकार हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दे रही है। देश में नए बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइसेस के पार्क भी बनाए जा रहे हैं। इनमें रोजगार के अनेक नए अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं।

जल जनित बीमारियों के बचाव के उद्देश्य से, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की दृष्टि से, ताकि दूषित जल पीने से होने वाली बीमारियों से नागरिकों की रक्षा की जा सके, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 से जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है और अभी तक 15 करोड़ परिवारों (भारत की 80 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या) को इस योजना के अंतर्गत नलों के माध्यम से शुद्ध जल उपलब्ध कराया जा चुका है।

स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की दृष्टि से भारत में निवासरत नागरिक एक तरह से स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। अन्यथा, अन्य कई विकसित देशों में आज स्वास्थ्य सेवाएं न केवल अत्यधिक महंगी दरों पर उपलब्ध हो रही हैं बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं का समय पर उपलब्ध होना भी बहुत मुश्किल हो रहा है।

अमेरिका में किसी नागरिक को यदि किसी डॉक्टर से अपाइंटमेंट लेना हो तो कभी कभी तो एक माह तक इसका इंतजार करना होता है। इमर्जेन्सी की स्थिति में विशेष इमर्जेन्सी अस्पताल में दिखाना होता है, जहां अत्यधिक महंगी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होती है। यदि किसी नागरिक के पास स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध नहीं है तो सम्भव है कि पूरे जीवन भर की कमाई इन विशेष इमर्जेन्सी अस्पतालों में खर्च हो जाए। अतः स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में अमेरिका में आज डॉक्टर को दिखाकर दवाई लेना अति मुश्किल काम है। इन विकसित देशों के विपरीत, भारत में तो किसी भी मोहल्ले में डॉक्टर को बहुत आसानी से दिखाया जा सकता है एवं तुरंत दवाई ली जा सकती है। आज अमेरिका में स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि वहां के नागरिक बीमार होने की स्थिति में, स्थानीय डॉक्टर से चूंकि तुरंत समय नहीं मिल पाता है अतः, ये बीमार नागरिक आस पास के देशों में जाकर अपना इलाज करा रहे हैं। अमेरिका सहित अन्य विकसित देशों में बिना मेडिकल बीमा के आप इन देशों में जिंदा नहीं रह सकते। अब आप कल्पना करें कि भारत में इलाज कराना कितना आसान है एवं वास्तव में ही इस दृष्टि से हम भारत में एक तरह से स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। कुल मिलाकर, देश में उत्तम स्थिति तो यह होनी चाहिए कि देश के नागरिक बीमार ही नहीं पड़ें, यह तभी सम्भव है जब देश के नागरिक अपनी सनातन संस्कृति के संस्कारों का नियमित रूप से अनुपालन पुनः प्रारम्भ करें। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो केंद्र एवं राज्य सरकारों को नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इसी प्रकार अपने बजट में बहुत बड़ी राशि का प्रावधान करते रहना पड़ेगा।

न्यायिक प्रक्रिया में सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता हो

ललित गर्ग

भारत की न्याय प्रणाली विसंगतियों एवं विषमताओं से घिरी है। न्याय–व्यवस्था जिसके द्वारा न्यायपालिकाएं अपने कार्य–संचालन करती है वह अत्यंत महंगी, अतिविलंबकारी और अप्रत्याशित निर्णय देने वाली है। 'न्याय प्राप्त करना और इसे समय से प्राप्त करना किसी भी राज्य व्यवस्था के व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार होता है।' 'न्याय में देरी न्याय के सिद्धांत से विमुखता है।' एक ही प्रकृति के मामलों में अलग–अलग फैसले आना, कुछ न्यायाधीश कभी–कभी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर मामलों को चुनते देखे जाते हैं, कुछ वकीलों को केस असाइनमेंट और सुनवाई के समय के मामले में तरजीह दी जाना, आंशिक सुनवाई के मामलों की प्रथा आदि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में विद्यमान चुनौतियों एवं विसंगतियों को दूर करने के लिये न्याय प्रक्रिया में आमूल–चूल परिवर्तन की अपेक्षा है। हाल ही में यह बात सामने आई है कि एक मौजूदा न्यायाधीश के आवास पर बड़ी मात्रा में नकदी पाई गई। इस तरह की घटना, किसी भी चल रही जांच के बावजूद, न्यायपालिका की ईमानदारी और निष्पक्षता पर एक बदनुमा दाग है।

न्यायपालिका ईमानदारी, निष्पक्षता और कानून के समक्ष समान व्यवहार के मूल्यों पर आधारित लोकतंत्र के चार स्तंभों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्तंभ है। न्यायालयों की ईमानदारी में जनता और कानूनी समुदाय का विश्वास बहाल करने के उद्देश्य से कानून में क्रांतिकारी बदलाव की अपेक्षा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इसके लिये तत्पर है और वे न्याय–प्रक्रिया की कमियों एवं मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, उनमें सुधार के लिये जागरूक दिखाई दे रहे हैं। निश्चित ही उनसे न्यायपालिका में छाये अंधेरे सायों में सुधार रूपी उम्मीद की किरणें दिखाई देने लगी है। स्वल्प समय में ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में वे कई महत्त्वपूर्ण फैसलों के कारण चर्चा में हैं। प्रधान न्यायाधीश के रूप में उन्होंने देश की न्यायपालिका के आमूल–चूल स्वरूप में परिवर्तन पर खुलकर जो विचार रखे हैं, वे साहसिक एवं दूरगामी सोच से जुड़े होने के साथ आम लोगों की धारणा से मेल खाते हैं। नया भारत बनाने एवं सशक्त भारत बनाने के लिये न्यायिक प्रक्रिया में सुधार सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खन्ना के सामने अनेक चुनौतियां हैं, उनका मार्ग कंटकाकीर्ण हैं। उनके द्वारा शुरु किये कानून सुधार–अभियान की किसी पहल का विरोध होना स्वाभाविक है। न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए कॉलेजियम सिस्टम पर भी सवाल उठाए गए। न्यायिक प्रणाली, जो निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों पर टिकी हुई है, न केवल निंदा से परे होनी चाहिए बल्कि जनता द्वारा भी देखी जानी चाहिए। न्यायालयों के भीतर एक व्यापक आत्मनिरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायिक प्रक्रिया बेदाग रहे और न्यायपालिका के बारे में जनता की धारणा को उसके सही परिप्रेक्ष्य पर बहाल किया जा सके। न्यायालयों की निष्पक्षता में आम आदमी का विश्वास सर्वोपरि है, और इस विश्वास को खतरे में डालने वाली किसी भी घटना से शीघ्रता और विवेकपूर्ण तरीके से निपटा जाना चाहिए।

न्यायालयों के कामकाज की पवित्रता बनाए रखने के लिए उनकी समीक्षा की जानी जरूरी है। यह बहुत स्पष्ट है कि कुछ न्यायाधीश, कभी–कभी, व्यक्तिगत पसंद के आधार पर मामलों चुनते देखे जाते हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया की एकरूपता और निष्पक्षता को कमजोर करता है। निष्पक्षता सुनिश्चित करने और पक्षपात या पक्षपात की किसी भी झलक से बचने के लिए मामलों का चयन करने का विवेक सीमित होना चाहिए। यह आवश्यक है कि सभी मामलों को एक स्थापित, पारदर्शी रोस्टर प्रणाली के आधार पर निष्पक्ष रूप से आवंटित किया जाए। यह भी न्याय–प्रक्रिया की एक बड़ी विसंगति है कि कुछ वकीलों को केस असाइनमेंट और सुनवाई के समय के मामले में तरजीह दी जाती है। इस तरह की प्रथाएं न्याय की नींव को ही नुकसान पहुँचाती हैं, क्योंकि वे अनुचित पक्षपात का कारण बन सकती हैं। किसी भी वकील को, चाहे उनकी स्थिति या पद कुछ भी हो, न्यायिक प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

सर्वप्रथम तो भारत के न्यायपालिका का संस्थागत चरित्र बदलने की जरूरत है। यह सामंती है और इसे इसके स्थान पर लोकतांत्रिक बनाना होगा। संवैधानिक जजों की चयन प्रक्रिया बहुत ही अलोकतांत्रिक है, जिसमें संविधान में वर्णित 'हम भारत के लोग' इनकी कोई भूमिका नहीं है।

यहां पहले से पदासीन चले आ रहे लोग अपनी पसंद के लोगों को चुनकर पदों पर बिठा देते हैं, देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में भारत का पूरा न्यायिक तंत्र कुछ परिवारों के कब्जे में आ गया है। वर्तमान सरकार ने परिवारवादी राजनीति के साथ परिवारवादी न्याय–व्यवस्था में सुधार किये हैं। आजादी के अमृत महोत्सव की चौखट पार कर चुके देश की न्याय व्यवस्था अभी तक औपनिवेशिक शिकंजे में जकड़ी हुई है। उच्चतर न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी है तो अधिकांश निचली अदालतों की कार्रवाई और पुलिस विवेचना की भाषा उर्दू है। वह आम आदमी के पल्ले नहीं पड़ती।

समय आ गया है कि यह सब आम आदमी की भाषा में हों। वर्षों–वर्ष चलने वाले मुकदमों का खर्च भी बहुत ज्यादा है। न्याय प्रक्रिया की कोई सीमा–अवधि नहीं है। इसलिए निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक समस्त न्यायालयों को दो पालियों में चलाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। नए न्यायालय भी स्थापित किए जाने चाहिए।

दक्षिण राज्यों के साथ अन्याय... परिसीमन पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के समर्थन में उतरे केटीआर

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (केटीआर) ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास की कड़ी निंदा की है. इसे एक अन्यायपूर्ण कदम बताया है, जिससे दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय कमी आएगी. स्टालिन ने शनिवार को परिसीमन को लेकर चेन्नई में बैठक बुलाई है. केटीआर इस बैठक में शामिल होने चेन्नई पहुंचे.

केटीआर ने चेतावनी दी कि यदि इस मुद्दे को तुरंत संबोधित नहीं किया गया, तो इसके दीर्घकालिक परिणाम होंगे, और आने वाली पीढ़ियां वर्तमान नेतृत्व को उसकी चुप्पी के लिए माफ नहीं करेंगी. चेन्नई में मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने दोहराया कि बीआरएस परिसीमन प्रस्ताव का कड़ा विरोध करता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस कदम से गंभीर क्षेत्रीय असमानताएं पैदा होंगी, राष्ट्रीय नीति निर्माण में दक्षिण भारतीय राज्यों की आवाज कमजोर होगी और केंद्रीय निधियों तक उनकी पहुंच कम होगी. उन्होंने सभी क्षेत्रीय दलों से एक साथ आने और इस अनुचित प्रस्ताव के खिलाफ एकजुट लड़ाई लड़ने का आह्वान किया.

उन्होंने चेतावनी दी, "इस परिसीमन का प्राथमिक प्रभाव दक्षिण भारत के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी होगी. यह मौजूदा क्षेत्रीय असंतुलन को और गहरा करेगा और दक्षिणी राज्यों को राष्ट्रीय मामलों में निर्णय लेने से और दूर कर देगा."

परिसीमन के मुद्दे पर स्टालिन के साथ खड़े हुए केटीआर

उन्होंने बताया कि तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य आर्थिक विकास, औद्योगीकरण और सामाजिक विकास में सबसे आगे रहे हैं. केटीआर ने कहा, "देश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद, इन राज्यों को अब इस राजनीतिक चाल के माध्यम से निशाना बनाया जा रहा है. यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार संसद और शासन में दक्षिण भारत की आवाज को कमजोर करने की कोशिश कर रही है."

केटीआर ने कहा कि दक्षिण भारतीय राज्यों ने सतत विकास पर राष्ट्रीय और वैश्विक सिफारिशों का पालन करते हुए वर्षों से प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को लागू किया है. हालांकि, नए परिसीमन अभ्यास के तहत, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित रखने में उनकी सफलता के लिए इन राज्यों को दंडित किया जा रहा है.

उन्होंने सवाल किया, "यह कदम मौलिक रूप से अनुचित है, जबकि जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया है, उन्हें अतिरिक्त सीटों और राजनीतिक प्रभाव से पुरस्कृत किया जाएगा, जिन्होंने जिम्मेदारी से काम किया है, उन्हें दंडित किया जा रहा है.

पटियाला में कर्नल और बेटे के साथ मारपीट मामले में नई एफआईआर, जांच के लिए एसआईटी गठित

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

पटियाला में 13 मार्च को नशे में धुत कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा भारतीय सेना के मौजूदा कर्नल पुष्पिंदर सिंह व उनके बेटे को पीटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. शुक्रवार को देर शाम को कर्नल पुष्पिंदर सिंह और उनके बेटे के साथ मारपीट मामले में नई एफआईआर दर्ज की गई है. थाना सिविल लाइन में आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है. मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. मामले की जांच एसपीएस परमार के नेतृत्व में होगी. कर्नल के परिवार को सुरक्षा भी दी गई है. वहीं, मामले में आरोपी सभी पुलिसकर्मियों का पटियाला से बाहर ट्रांसफर भी कर दिया गया है.

एसआईटी में अतिरिक्त पुलिस महा. निदेशक कानून एवं व्यवस्था, पंजाब, एसपीएस के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय विशेष जांच दल (ैप्) का गठन किया गया है. कमेटी में संदीप मलिक, आईपीएस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हो. शियारपुर और मनप्रीत सिंह पीपीएस, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, एसएएस को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है.

मामले में नई एफआईआर दर्ज

इस मामले को लेकर पंजाब के स्पेशल क्लच अर्पित शुक्ला का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि इस मामले में एक नई एफआईआर दर्ज की गई है. इसके अलावा मामले की जांच के लिए नई एसआईटी का गठन भी किया गया है. ैच् परमार ।क्लच लॉ एंड ऑर्डर ैप् को हेड करेंगे. वहीं, एसएसपी होशियारपुर और मो. हाली के एसपी एसआईटी के मेंबर होंगे.

घटना में शामिल पुलिस अधिकारियों का जिले के बाहर तबादला

पुलिस ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इस केस में शामिल पुलिस अधिकारियों का जिले के बाहर ट्रांसफर कर दिया गया है. दूसरी ओर से ।क्लच सिक्योरिटी को कर्नल के परिवार की सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई. इस मामले को लेकर पंजाब के विधानसभा में हंगामा देखने को मिला. कांग्रेस के विधायक प्रताप बाजवा ने कहा कि पंजाब में सैनिक सुरक्षित नहीं है. उन्होंने मांग की कि पटियाला में कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ पर हमला करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और उन्हें बर्खास्त किया जाए.

बेटे के साथ खाना खाने आए थे कर्नल विधानसभा में बाजवा ने कहा कि सेना के कर्नल 13 मार्च को अपने बेटे के साथ खाना खाने आए थे. उनकी पत्नी के अनुसार 12 पुलिस अधिकारी सादे वर्दी में आए और पार्किंग को लेकर विवाद करने लगे. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने कर्नल के साथ मारपीट की और उनकी पगड़ी भी उतार दी.

मुस्लिम भाइयों को कोई आंख दिखाएगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं... महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा बयान

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

महाराष्ट्र में औरंगजेब विवाद में हुई नागपुर हिंसा को लेकर माहौल गरमाया हुआ है. पुलिस की जांच जारी है और सियासी बयानबाजी भी तेज है. मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के कई नेताओं का कहना है कि हिंसा के दौरान पुलिस पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. इस बीच सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, मुस्लिम भाइयों को कोई भी आंख दिखाएगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं. फिर चाहे कोई भी हो.

महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपनी पार्टी एनसीपी की तरफ से रोजा इफ्तार का आयोजन किया था.

इस दौरान उन्होंने मुस्लिमों को भरोसा दिलाया कि जो भी मुस्लिम भाइयों को आंख दिखाएगा, दो समूहों के बीच संघर्ष भड़काकर कानून व्यवस्था को बाधित करेगा और कानून को अपने हाथ में लेने की को. शिश करेगा, उसे किसी भी हालत में बख्शा या माफ नहीं किया जाएगा.

रमजान सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं

अजित पवार ने ये भी कहा कि रमजान सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं है. यह हमें एकता और भाईचारे का संदेश देता है. जरूरतमंदों की पीड़ा को समझने की प्रेरणा देता है. भारत विविधता में एकता का प्रतीक है. बता दें कि एनसीपी अजित पवार गुट की तरफ से मुंबई शहर के इस्लाम जिम खाना में मुसलमाना. ै के पाक माह रमजान पर इफ्तारी का आयोजन हुआ. इस मौके पर अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, सना मलिक, नवाब मलिक सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे.

बता दें कि अजित पवार का ये बयान उस वक्त आया है जब महाराष्ट्र में माहौल गरमाया हुआ है.

नागपुर शहर में हुई हिंसा मामले में शुक्रवार को 14 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है. अब तक इस मामले में पकड़े गए लोगों की कुल संख्या 105 हो गई है. हिंसा मामले में 10 किशोर भी हिरासत में लिए गए हैं.

संसद की पीएसी बैठक में हंगामा, स्वदेश दर्शन स्कीम के आंकड़ों पर सांसदों ने उठाया सवाल

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

संसद की पब्लिक एकाउंटस कमेटी (पीएसी) बैठक में स्वदेश दर्शन स्कीम पर विपक्षी दलों ने अधिकारियों को घेरा, तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी जमकर सवाल उठाए. बता दें कि पब्लिक एकाउंटस कमेटी का मुखिया विपक्षी दल का नेता होता है, जो कि कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल हैं.

सूत्रों के मुताबिक, पीएसी की बैठक में चौयरमैन केसी वेणुगोपाल ने पर्यटन सचिव, सहसचिव और ेप् डायरेक्टर से स्वदेश दर्शन स्कीम का ताजा डेटा मांगा, तो अफरा तफरी हो गयी. दरअसल, सरकारी बाबुओं ने कहा कि, 76 में से 75 प्रोजेक्ट पूरे हो गए. बस इस पर विपक्षी ही नहीं सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी सवाल खड़े कर दिए. इन मुद्दों पर एकजुट दिखा पक्ष विपक्ष

सांसदों ने एकजुट होकर कहा कि बिहार में बुद्धिष्ट सर्किट, तेलंगाना में ट्राइबल सर्किट, झारखंड में कांवड़ सर्किट का काम अधूरा है. कई जगह ठीक तरह से डीपीआर तक तैयार नहीं है. वहीं सीएजी रिपोर्ट हमारी शिकायतों को धार दे रही हैं, इसलिए इस पर जल्दी और गम्भीरता से ध्यान दिया जाए. उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्रालय प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं कर पा रहा, क्योंकि, पर्यटन मंत्रालय के साथ संस्कृति, फारेस्ट जैसे मंत्रालयों में समन्वय नहीं है.

पानीपत में सनसनीखेज वारदात, जेजेपी नेता रविंद्र मिन्ना की गोली मारकर हत्या

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

हरियाणा के पानीपत में जननायक जनता पार्टी (जेज. ेपी) नेता रविंद्र मिन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. इस वारदात को विकास नगर में अंजाम दिया गया है. बताया जा रहा है कि मिन्ना के सिर में गोली मारी गई है. फायरिंग में दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनक. ो अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अभी तक हमलावरों का पता नहीं चल सका है.

साल 2014 के विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी नेरविंद्र मिन्ना को पानीपत शहर सीट से टिकट दिया था. हालांकि, उनका टिकट काटकर बाद में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी रोहिता रेवड़ी को समर्थन दे दिया था. इसके साथ ही रविंद्र भी भाजपा में शामिल हो गए थे. हालांकि, कुछ समय बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहकर फिर से जेजेपी का दामन थाम लिया था.

संपादकीय

यूक्रेन युद्धविराम विवाद

यूक्रेन पर ट्रंप–पुतिन वार्ता में नवीनतम घटनाक्रम से पता चलता है कि शांति की ओर कोई भी रास्ता कितना कठिन और सशर्त है। बहुत अधिक प्रत्याशा के बाद, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर रूसी हमलों को रोकने के लिए केवल एक सीमित विराम पर सहमति व्यक्त की है। पूर्ण युद्धविराम प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करने से वर्तमान में चल रही वार्ता की जटिलता और नाजु. कता दोनों को रेखांकित किया गया है। जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में चित्रित करते हैं, वास्तविकता इसके विपरीत बताती हैरू यह स्थायी शांति की ओर एक कदम कम और मास्को के हितों की सेवा के लिए बनाया गया एक सामरिक विराम अधिक है। श्री पुतिन द्वारा ष्ऊर्जा युद्धविरामष् को स्वीकार करने के साथ कई शर्तें जुड़ी हुई हैं। किसी भी व्यापक युद्धविराम के लिए यूक्रेन को सभी विदेशी सैन्य सहायता और खुफिया सहायता को समाप्त करने की उनकी मांग नई नहीं है ़ लेकिन इसे नए सिरे से जोर देकर दोहराया गया है। कीव और उसके यूरोपीय समर्थकों के लिए, यह अभी भी एक गैर–शुरुआत है। श्री पुतिन की शर्तें युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक जाती हैं; उनका उद्देश्य यूक्रेन को रणनीतिक रूप से अलग–थलग करना और उसे असुरक्षित छोड़ना है। यह गतिशीलता वार्ता में एक स्थायी विषमता को दर्शाती है, जहाँ मास्को अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए लाभप्रद शर्तें निर्धारित करना जारी रखता है। श्री ट्रम्प, अपने हिस्से के लिए, तत्काल और व्यापक युद्ध विराम पर पहले के आग्रह से हटकर आंशिक युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। ऐसा करने में, अमेरिका की स्थिति उस स्थिति से पीछे हट गई है जो एक सप्ताह पहले ही सुरक्षित थी जब वाशिंगटन ने कीव को 30 दिनों के पूर्ण युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमत होने के लिए राजी किया था। अब वह समझौता श्री पुतिन की संकीर्ण पेशकश के पक्ष में टलता हुआ दिखाई देता है, जिससे वाशिंगटन के प्रभाव और उसकी कूटनीतिक रणनीति की सुसंगतता पर संदेह पैदा होता है। श्री ट्रम्प द्वारा इस आह्वान को ष्उत्पादकष् के रूप में प्रस्तुत करना अधिक परेशान करने वाली वास्तविकता को छुपाता हैरू अमेरिका यूक्रेन से व्यापक रियायतों के बदले में वृद्धिशील, प्रतीकात्मक इशारों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। कीव के लिए, निहितार्थ परेशान करने वाले हैं। राष्ट्रपति वोलोडिमर ज़ेलेंस्की ने ऊर्जा अवसंरचना को कवर करने वाले युद्ध विराम के विचार का सावधानीपूर्वक स्वागत किया है, लेकिन तुरंत ही रूसी ड्रोन हमलों की ओर इशारा किया है ़ जिसमें अस्पतालों और नागरिक बिजली आपूर्ति पर हमले शामिल हैं ़ जो कि बुरे विश्वास का सबूत है। यूक्रेन का नेतृत्व श्री पुतिन के कदम को समय खरीदने, अपनी स्थिति को मजबूत करने और सार्थक समझौता किए बिना आगे की रियायतें प्राप्त करने के तरीके के रूप में देखता है। क्रेमलिन का कथन ़ कि एक ष्जटिल, स्थिर और दीर्घकालिकष् समझौते के लिए यूक्रेन के लिए पश्चिमी समर्थन को समाप्त करना आवश्यक है ़ श्री पुतिन के इरादों को उजागर करता है। जर्मनी और यूके सहित यूरोपीय नेताओं ने यूक्रेन की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करके और पूर्ण युद्ध विराम का आह्वान करके प्रतिक्रिया व्यक्त की है। लेकिन इन वार्ताओं की गति अनिश्चित बनी हुई है। श्री ट्रम्प की समर्थन वापस लेने की स्पष्ट इच्छा ने मास्को को प्रोत्साहित किया है, जबकि कीव को सुरक्षा की गारंटी के बिना कठिन निर्णय लेने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। अंततः, ट्रम्प–पुतिन कॉल में सहमति से लिया गया नाजुक विराम विलंबित संकल्पों और लाल रेखाओं को बदलने वाले संघर्ष में एक और अध्याय बनने का जोखिम उठाता है। यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमलों से थोड़ी राहत दे सकता है, लेकिन यह एक स्थायी शांति से बहुत दूर है। क्या यह वास्तविक वार्ता की शुरुआत का संकेत देता है या मास्को द्वारा सिर्फ एक और भू–राजनीतिक शतरंज चाल है, यह देखना बाकी है।

अवसाद और बेचौनी जैसी मानसिक समस्याओं से जूझ रहे बच्चे

दीपक कुमार त्यागी

आजकल की भाग.दौड़ वाली दुनिया में मानसिक समस्याएं बड़ी तेजी से लोगों को अपना शिकार बनाती जा रही हैं। इसका प्रभाव इतना तीक्ष्ण और विकराल होता है कि इससे न तो कोई देश बचा है, और न ही कोई राज्य... इसके घातक प्रभाव से अछूता आज न तो कोई गांव है, न कोई शहर और न ही कोई गली.मोहल्ला। इसका शिकार बच्चे, किशोर, बड़े, वृद्ध, स्त्री और पुरुष सभी हो रहे हैं, लेकिन आंकड़ों की बात करें तो विशेष रूप से, बच्चों और किशोरों में यह समस्या कुछ ज्यादा ही जटिल होती जा रही है। गौरतलब है कि इसके कारण बच्चों की मासूमियत खत्म होती जा रही है। उनकी फूल.सी मुस्कराहट कहीं खोती जा रही है। वे बेहद गुस्सैल होते जा रहे हैं। वे बात. बात पर क्रोध करने लगे हैं। उनकी बात नहीं सुनी और मानी जाए तो वे आपे से बाहर हो जाते हैं। यहां तक कि कई बार तो अपने माता.पिता और अभिभावक के ऊपर हमले करने से भी वे नहीं चूकते। जाहिर है कि ऐसे में उनके माता.पिता को यह समझ में ही नहीं आता कि जो बच्चे कुछ महीने, साल पहले तक मासूमियत से भरे बिल्कुल सामान्य व्यवहार वाले थे, हर पल खेलते.कूदते, हंसते.मुस्कराते, गाते. गुनगुनाते और आयु के अनुरूप शरारतें करते रहते थे, आखिर क्या कारण है कि अचानक उनका व्यवहार इस प्रकार बदल गया कि वे उन्हें बिल्कुल सुनना और मानना ही नहीं चाहते।

इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहा जाए कि खेलने.कूदने और खाने.पीने की आयु में देश के बच्चों और किशोरों में बैचेनी, डिप्रेशन और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं आज गंभीर से गंभीरतम रूप लेती जा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) की श्मेन्टल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपलश नामक ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 10 से 19 वर्ष का प्रायः प्रत्येक सातवां बच्चा किसी.न.किसी प्रकार की मानसिक समस्या से जूझ रहा है। इन समस्याओं में अवसाद, बेचौनी और व्यवहार से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी लगभग एक तिहाई समस्याएं 14 साल की उम्र से पहले शुरू हो जाती हैं, जबकि इनमें से आधी समस्याएं 18 वर्ष से पहले सामने आने लगती हैं। तात्पर्य यह कि जब हमारे मासूम बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर कदम बढ़ना आरंभ करते हैं, सामान्यतः उसी दौरान मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अलग.अलग समस्याएं उन्हें अपना शिकार बनाना शुरू कर देती हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 07 बच्चों में से एक बच्चा डिप्रेशन का शिक. ार है। आंकड़ों की बात करें तो देश के 14 प्रतिशत बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य खराब है। इसी प्रकार, श्इंडियन जर्नल ऑफ साइकिएट्रीश में वर्ष 2019 में प्रका. शित एक अध्ययन के अनुसार भारत में 05 करोड़ से अधिक बच्चे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे।

गौरतलब है कि इनमें से ज्यादातर बच्चे एंग्जाइटी और डिप्रेशन का सामना कर रहे थे। यूनिसेफ के एक अनुमान के मुताबिक कोरोना महामारी के बाद ये आंकड़े पहले की तुलना में कई गुना अधिक बढ़े हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में 30 करोड़ से भी अधिक लोग एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं और 28 करोड़ लोग डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं। विज्ञान आधारित दुनिया भर में प्रसिद्ध जर्नल श्द लैंसेट साइकिएट्रीश में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में 75 प्रतिशत टीनएजर्स एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। वहीं, 10 से 18 वर्ष की आयु के 64 प्रतिशत वयस्कों को तीन से अधिक बार खराब मानसिक स्वास्थ्य का दंश झेलना पड़ा है। विशेषज्ञों के अनुसार किशोरावस्था के दौरान लड़के.लड़कियों में कई प्रकार के हॉर्मोनल और शारीरिक बदलाव होते हैं। इसके कारण उनके सोच और व्यवहार में बदलाव आता है। इनके अतिरिक्त, उसी दौरान उन लड़के. लड़कियों को बोर्ड परीक्षाओं एवं कॅरियर को लेकर कोर्स सिलेक्शन जैसे दबावों और उहापोह वाली परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। ऐसे में, यदि उन्हें घर और स्कूल में उनके मनोनुकूल अथवा कहा जाए कि सहयोगी परिवेश नहीं मिले तो ये दबावों और उहापोह वाली परिस्थितियां प्रायः एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रूप ले लेती हैं। इसी प्रकार, जो बच्चे लगातार पढ़ाई.लिखाई नहीं करते हैं, वे परीक्षाओं के आने पर अक्सर दबाव में आ जाते हैं। वहीं, मनोचिकित्सकों का मानना है कि आजकल बच्चों में फेलियर हैंडल करने की क्षमता भी कम होती जा रही है। कभी.कभी इसके कारण जेनेरिक भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारी प्रतिदिन की आदतों में शामिल हो चुके फास्ट फूड, शुगरी ड्रिंक्स और सोशल मीडिया जैसे तत्व भी भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन का कारण बन रहे हैं। साल 2024 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन में यह बात सामने आई थी कि जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एवं फास्ट फूड खाने से व्यक्ति में एंग्जाइटी और डिप्रेशन का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। उक्त अध्ययन के अनुसार इसका सबसे अधिक खतरा वयस्कों को होता है, क्योंकि फास्ट फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के सबसे बड़े उपभोक्ता भी वही होते हैं। ऐसे ही, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में 2022 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार चीनी से बने अथवा शुगरी ड्रिंक्स भी का सेवन किशोरों के खराब मानसिक स्वास्थ्य की बड़ी वजह बन रहा है। जाहिर है कि एनर्जी ड्रिंक या कोल्डड्रिंक के नाम पर मिल रहे इस प्रकार के पेय पदार्थ एंग्जाइटी और डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं। वहीं, साइंटिफिक जर्नल फ्रंटियर्स में 2023 में प्रकाशित एक अध्ययन में यह खुलासा हुआ था कि जो टीनएजर प्रतिदिन 07 घंटे से अधिक समय तक स्क्रीन पर व्यतीत करते हैं, उन्हें डिप्रेशन का शिकार बनने की आशंका अन्य टीनएजर्स की तुलना में दोगुने से भी अधिक होती है।

उक्त अध्ययन में यह भी बताया गया था कि यदि कोई सोशल मीडिया पर प्रतिदिन एक घंटे बिता रहा है तो प्रत्येक घंटे के हिसाब से व्यक्ति में डिप्रेशन के लक्षण प्रतिवर्ष 40 प्रतिशत तक बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार, बीएमसी मेडिसिन में 2010 में प्रका. शित एक अध्ययन में यह पता चला था कि जो लड़के.लड़कियां किसी तरह के खेल, शारीरिक व्यायाम या फिजिकल एक्टिविटी में भाग नहीं लेते, उनके डिप्रेशन का शिकार बनने की आशंका अधिक होती है। उक्त अध्ययन में यह भी यह भी मालूम हुआ था कि प्रतिदिन एक घंटे शारीरिक व्यायाम या फिजिकल एक्टिविटी करने से डिप्रेशन एवं एंग्जाइटी का जोखिम 95 प्रतिशत तक कम हो जाता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि बच्चों का स्पोर्ट्स टाइम बढ़ाने और स्क्रीन टाइम घटाने का हरसंभव प्रयास किया जाए। लेकिन जो बच्चे पहले ही एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार बन चुके हैं, उन्हें ठीक करने के लिए तत्काल सभी आवश्यक कदम उठाए जाने की जरूरत है। वैसे, देखा जाए तो मस्तिष्क का विकास लाइफस्टाइल एवं अनुभव के आधार पर होता है। इसलिए बच्चों को रियलिस्टिक बनाएं। उन्हें जीवन की वास्तविकताओं से अवगत कराएं। उनके साथ जीवन के उतार.चढ़ाव को साझा करें। साथ ही, प्रतिदिन दो बार परिवार के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें और यदि दो बार संभव नहीं हो तो कम.से.कम एक बार का भोजन पूरा परिवार साथ में करें।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान मोबाइल और टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी बनाकर रखें। ऐसा करने से परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा। गौरतलब है कि बच्चों से जुड़े मामलों से संबंधित शोध एवं अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध शोध संस्थान श्मरडोक चिल्ड्रेन्स रिसर्च इंस्टीट्यूटश के तत्वावधान में किए गए इस अध्ययन में यह बताया गया है कि इन मामलों में क्लिनकिल केयर से अधिक जरूरत बच्चों को इन मानसिक बीमारियों से बचाने को लेकर स्ट्रेटजी बनाए जाने की है।

वहीं, डब्ल्यूएचओ एवं यूनिसेफ की श्मेन्टल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपलश नामक रिपोर्ट में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए समुदाय आधारित मॉडल तैयार करने की बात कही गई है।

. चेतनादित्य आलोक,
वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, स्तंभकार,
आध्यात्मिक चिंतक एवं वास्तु ज्ञाता,
रांची, झारखंड (इस लेख में लेखक के
अपने विचार हैं।)

भूख की जड़ से लड़ाई : भोजन की बर्बादी से निपटना जरूरी

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : ऐसी दुनिया में जहाँ लाखों लोग भूख से पीड़ित हैं, खाद्य असुरक्षा और बड़े पैमाने पर खाद्य बर्बादी का विरोधाभासी सह–अस्तित्व वैश्विक अक्षमता का एक स्पष्ट अभियोग है। भूख को संबोधित करने के लिए न केवल खाद्य उत्पादन के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, बल्कि हमारे समाजों में व्याप्त खाद्य बर्बादी के भयावह स्तरों से निपटने के लिए एक ठोस प्रयास की भी आवश्यकता है। खाद्य बर्बादी के खिलाफ लड़ाई सिर्फ़ एक पर्यावरणीय अनिवार्यता नहीं है; यह एक नैतिक दायित्व है और भूख के अभिशाप को कम करने का एक सीधा रास्ता है जो अनगिनत लोगों को परेशान करता है। भोजन की बर्बादी का स्तर चौंका देने वाला है, हर साल मानव उपभोग के लिए उत्पादित सभी खाद्य पदार्थों में से लगभग एक तिहाई बर्बाद हो जाता है। यह बर्बादी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों में होती है – उत्पादन और वितरण से लेकर खुदरा और उपभोक्ता स्तर तक। भूख की समस्या को सही मायने में संबो. धित करने के लिए, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि दुनिया भर में बर्बाद होने वाला भोजन भूखी आबादी को कई गुना पोषण दे सकता है।

भोजन की बर्बादी को कम करना संसाधन संरक्षण का मात्र एक प्रयास नहीं है; यह भूख के मानवीय संकट का एक ठोस समाधान है। जब खाने योग्य भोजन को फेंक दिया जाता है, तो यह न केवल संसाधनों की बर्बादी को दर्शाता है, बल्कि जरूरतमंद लोगों को भोजन से वंचित करना भी दर्शाता है। खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे समुदायों को अधिशेष भोजन को पुनर्निर्देशित करके, हम प्रचुरता और कमी के बीच की खाई को पाट सकते हैं, और बर्बादी को भूखे लोगों के लिए जीवन रेखा में बदल सकते हैं।

खाद्यान्न की बर्बादी से निपटने के प्रयासों को आपूर्ति श्रृंखला की जड़ों से शुरू करना चाहिए। किसान, जो फसल उगाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, अक्सर वितरण और भंडारण में चुनौतियों का सामना करते हैं, जिससे उनकी उपज बाजार में पहुंचने से पहले ही काफी नुकसान हो जाता है। भंडारण और परिवहन को अनुकूलित करने वाले बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकियों में निवेश करके इन नुकसानों को कम किया जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि श्रम का फल खेतों में सड़ने के बजाय इच्छित उपभोक्ताओं तक पहुंचे।

खुदरा क्षेत्र में, जहाँ समाप्ति तिथियाँ और सौंदर्य मानक महत्वपूर्ण बर्बादी में योगदान करते हैं, सुधार के लिए एक अवसर है। लचीले मानकों और दान कार्यक्रमों को अपनाने को प्रोत्साहित करने से अधिशेष भोजन को धर्मार्थ संगठनों को पुनर्निर्देशित किया जा सकता है, जिससे अपशिष्ट को साम. ुदायिक पोषण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन में प्रभावी रूप से परिवर्तित किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता सूचित विकल्प बनाकर, बर्बादी को कम करने के लिए प्रतिबद्ध व्यवसायों का समर्थन करके और अपनी स्वयं की उपभोग आदतों के प्रति सचेत रहकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

आतिथ्य उद्योग, जो अपने उच्च स्तर के भोजन की बर्बादी के लिए कुख्यात है, अतिरिक्त भोजन को रोकने के लिए भाग नियंत्रण, मेनू अनुकूलन और बचे हुए भोजन का रचनात्मक उपयोग जैसे अभ्यास अपना सकता है।

व्यवसायों, गैर–लाभकारी संस्थाओं और सरकारों के बीच सहयोग प्रयासों को और अधिक सुव्यवस्थित कर सकता है, जिससे एक व्यापक दृष्टिकोण तैयार हो सकता है जो सभी क्षेत्रों में अपशिष्ट में कमी को लक्षित करता है।

भोजन की बर्बादी से निपटने और भूख को कम करने के बीच सहजीवी संबंध को पहचानना अनिवार्य है। ज़रूरतमंदों को अति. रिक्त भोजन वितरित करके, हम न केवल तत्काल पोषण संबंधी कमियों को दूर करते हैं, बल्कि समुदाय और साझा जिम्मेदारी की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। भूख को कम करने के साधन के रूप में अतिरिक्त भोजन का पुनः उपयोग करना केवल दान से कहीं बढ़कर है; यह एक अधिक न्यायसंगत और दयालु दुनिया के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

निष्कर्ष में, खाद्य अपशिष्ट के खिलाफ लड़ाई एक परिधीय चिंता नहीं है, बल्कि भूख के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक केंद्रीय रणनीति है।

अधिशेष संसाधनों को ज़रूरतमंदों तक पुनर्निर्देशित करने की नैतिक अनिवार्यता को स्वीकार करके, हम एक अधिक टिकाऊ और न्यायपूर्ण खाद्य प्रणाली की ओर एक रास्ता बना सकते हैं। एक समाज के रूप में, हमें यह पहचानना चाहिए कि भोजन की बर्बादी सिर्फ़ एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है – यह बुनियादी मानवीय गरिमा का अपमान है। आपूर्ति श्रृंखला के हर स्तर पर ठोस प्रयासों के माध्यम से, हम खाद्य अपशिष्ट से जुड़ी कहानी को बदल सकते हैं, इसे भूख से लड़ने और अधिक दयालु दुनिया बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण में बदल सकते हैं।

श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 26 मार्च को जनता के लिए खुलेगा, पर्यटन सीजन की शुरूआत

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

श्रीनगरः डल झील और जबरवान पहाड़ियों के बीच स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 26 मार्च को जनता के लिए खुल जाएगा, जो कश्मीर घाटी में पर्यटन सीजन की शुरुआत का प्रतीक होगा। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन की स्थापना तत्कालीन राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने 2007 में जम्मू और कश्मीर में पर्यटन सीजन को आगे बढ़ाने के लिए की थी, जो पहले गर्मियों और सर्दियों तक सीमित था। पूर्व में सिराज बाग

के रूप में जाना जाने वाला यह उद्यान जनता के लिए खोल दिया जाएगा क्योंकि विभिन्न रंगों के ट्यूलिप खिलने लगे हैं, पुष्प कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा। विभाग चरणबद्ध तरीके से ट्यूलिप बल्ब लगाता है ताकि फूल एक महीने या उससे अधिक समय तक खिले रहें। ट्यूलिप गार्डन के सहायक पुष्प कृषि अधिकारी आसिफ अहमद ने कहा, गार्डन को 26 मार्च को जनता के लिए खोल दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गार्डन का उद्घाटन करेंगे। अहमद ने कहा कि गार्डन के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं और इसे तैयार करने के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, हम हर साल ट्यूलिप गार्डन के लिए कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इस साल हम एक नई रंग योजना लेकर आ रहे हैं। हमने ट्यूलिप की दो नई किस्में जोड़ी हैं, जिससे कुल संख्या 74 हो गई है। हाइसिंथ, डेफोडिल, मस्करी और साइक्लेमेन जैसे अन्य वसंत फूल भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

अहमद ने कहा कि 55 हेक्टेयर में फैले इस गार्डन में लगभग 17 लाख ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं।

3 लीटर पानी और 5000 कदम, ऐसा करते हैं तो फिट रहेगी आपकी किडनी!

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

देश में हाल कि दिनों में किडनी की समस्या से काफी लोग ग्रसित हो रहे हैं. दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के विभागध्यक्ष डॉ. हिमांशु महापात्रा ने टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में बताया कि सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि किडनी की समस्या से पारम्परिक रुप से ग्रसित मरीज से इतर बच्चों में काफी परेशानी देखने को मिल रही है. उन्होंने कहा कि हाल फिलहाल के आंकड़े बताते हैं कि देश में बच्चो और किशोरों में खासकर किडनी की परेशानी तेजी से बढ़ रही है.

डॉ. हिमांशु ने कहा कि खास उम्र की बात करें तो खान पान और गलत लाइफस्टाइल की वजह से किशोरों में किडनी की परेशानी बढ़े हैं. आंकड़ों पर यदि गौर करें तो साल 2011–2017 के बीच किडनी डिजीज के मामले 11.2 प्रतिशत बढ़े, जबकि साल 2018–2023 के बीच किडनी डिजीज के मामले 16.38 प्रतिशत बढ़े.

आव्रजन विधेयक : जाली पासपोर्ट का उपयोग करने पर सात साल की जेल

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

नई दिल्ली : यदि संसद द्वारा नए आव्र. जन विधेयक को मंजूरी दे दी जाती है तो भारत में प्रवेश करने, रहने या बाहर जाने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को सात साल तक की जेल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संचालित इस विधेयक में होटलों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम द्वारा विदेशियों के बारे में सूचना देना अनिवार्य करने का प्रावधान है, ताकि निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरने वाले विदेशियों पर नजर रखी जा सके। सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों और

जहाजों को भारत में किसी बंदरगाह या स्थान पर यात्री और चालक दल की सूची, ऐसे विमान, जहाज या परिवहन के अन्य साधन पर सवार यात्रियों और चालक दल की अग्रिम सूचना भी प्रस्तुत करनी होगी। 11 मार्च को लोकसभा में पेश किए गए विधेयक के अनुसार, ष्जो कोई भी जानबूझकर जाली या धोखाधड़ी से प्राप्त पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज या वीजा का उपयोग या आपूर्ति भारत में प्रवेश करने या भारत में रहने या भारत से बाहर जाने के लिए करता है, उसे कम से कम दो वर्ष की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही कम से कम एक लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा, जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।ष

इसमें यह भी कहा गया है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति यदि वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज के बिना भारत के किसी क्षेत्र में प्रवेश करता है, जिसमें कानून के प्रावधानों या उसके अनुसरण में दिए गए किसी नियम या आदेश का उल्लंघन करते हुए ऐसे प्रवेश के लिए आवश्यक वीजा भी शामिल है, तो उसे पांच वर्ष तक के कारावास और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

नार्को–आतंकवाद में शामिल अपराधियों से सख्ती से निपटा जाएगा : जम्मू–कश्मीर के शीर्ष पुलिस अधिकारी

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू: जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) को 10,122 एकड़ से अधिक भूमि हस्तांतरित करने के आधी सदी बाद भी जम्मू–कश्मीर सरकार ने अभी तक 1,075 एकड़ प्रमुख भूमि का सीमांकन और कब्जा प्राधिकरण को नहीं सौंपा है।

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि सीमांकन का कार्य अभी भी जारी है। सरकारी दस्तावेज के अनुसार, ष्जेडीए को 80,976 कनाल 10 मरला (10,122 एकड़) भूमि हस्तांतरित की गई है, जिसमें से 35,353 कनाल 1 मरला नजूल भूमि है, जो 20 अक्टूबर 1973 के सरकारी आदेश के तहत हस्तांतरित की गई है।

लगभग 45,623 कनाल 9 मरला राज्य की भूमि है, जो जम्मू और सांबा जिलों में जम्मू और कश्मीर राज्य भूमि अधिनियम के तहत हस्तांतरित की गई है। इसमें आगे कहा गया है, ष्जेडीए की कुल 80,976 कनाल 10 मरला भूमि में से 32,387 कनाल 19 मरला जल निकायों के अंतर्गत है, 12,202 कनाल 19 मरला वन और खाद के अंतर्गत है, और 36,220 कनाल 4 मरला बंजर कदीम, कृषि और अन्य प्रकार की भूमि के अंतर्गत है।

सरकार ने लंबी सीमांकन प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए कहा, आज तक 72,373 कनाल 13 मरला (9,046.62 एकड़) भूमि का सीमांकन किया गया है, जिसमें से 8,602 कनाल 17 मरला (1,075.25 एकड़) भूमि का सीमांकन किया जाना बाकी है।

बजट सत्र 2025: सदन ने आईटी, एफसीएस एंड सीए, एआरआई प्रशिक्षण परिवहन, वाईएसएस, एस एंड टी विभागों के लिए अनुदान पारित किया

जम्मू लद्दाख विजन ब्यूरो

जम्मू : जम्मू–कश्मीर विधान सभा ने आज सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 2796.07 लाख रुपये, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के लिए 70312.76 लाख रुपये, एआरआई प्रशिक्षण, श्रम स्टेशनरी और मुद्रण के लिए 4048.90 लाख रुपये, परिवहन के लिए 12617.03 लाख रुपये, युवा सेवा और खेल के लिए 62154.91 लाख रुपये और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों के लिए 17279.10 लाख रुपये की अनुदान राशि पारित की।

सदन में दिन भर चली विस्तृत चर्चा के बाद अनुदान पारित कर दिए गए।

चर्चा का सारांश देते हुए मंत्री ने कहा कि जम्मू–कश्मीर सरकार समावेशी और परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए एक व्यापक डिजिटल परिवर्तन मिशन चला रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू–कश्मीर का आईटी विभाग क्षेत्र की डिजिटल क्रांति में सबसे आगे है, जो अत्याधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से शासन दक्षता, पारदर्शिता और नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए समर्पित है।

मंत्री ने बताया कि पिछले कई वर्षों में ऑनलाइन सेवाओं की संख्या लगभग 60 से बढ़कर 1166 हो गई है, साथ ही रैपिड असेसमेंट सिस्टम के माध्यम से नागरिकों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने और मोबाइल दोस्त, डिजी–लॉकर के साथ एकीकरण का प्रावधान भी किया गया है। सभी ऑनलाइन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार ऑटो अपील और ऑटो एस्केलेशन तंत्र के दायरे में लाया जा रहा है।

मंत्री ने कहा कि ई–गवर्नेंस उत्कृष्टता केंद्र, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, राज्य डेटा सेंटर में कंप्यूटर का विस्तार, डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करना कुछ प्रमुख पहल हैं जो एक प्रभावी एआई पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय करने और क्षेत्र में गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों का पोषण करने के अलावा अनुसंधान, विकास और नवाचार में निवेश करने के लिए शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि श्रज्ञैं।छ को जिला, तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों में क्षैतिज रूप से विस्तारित किया जाएगा। नई दिल्ली में श्र–ज्ञ हाउस सहित सभी सरकारी कार्यालयों में सरकारी वाई–फाई/इंट्रानेट को निर्बाध बनाया जाएगा। इसके अलावा, जिला मुख्यालयों में जिला लैन की स्थापना की जाएगी, उन्होंने कहा।

एलजी ने एबीवीपी की क्षेत्रीय समझ में छात्र अनुभव (एसईआरयू) पहल के तहत लद्दाख से आए युवा प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज एबीवीपी की राष्ट्रीय एकता यात्रा – क्षेत्रीय समझ में छात्र अनुभव (एसईआरयू) पहल के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के युवा प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की।

बातचीत के दौरान, भाग लेने वाले युवाओं ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की अपनी यात्राओं के दौरान प्राप्त अनुभव और जोखिम को साझा किया।

उपराज्यपाल ने लद्दाख के युवाओं को देश की सांस्कृतिक विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने, उन्हें शैक्षिक और शासन ढांचे के बारे में शिक्षित करने और श्एक भारत श्रेष्ठ भारतश के दृष्टिकोण को साकार करने में उनकी भूमिका को पहचानने का अवसर प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पहल की सराहना की। उन्होंने युवाओं को अपनी बधाई और शुभकामनाएँ दीं।

यह यात्रा युवाओं के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने, उनके बीच सांस्कृतिक समझ और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और युवाओं को उनके भविष्य के शैक्षणिक और करियर प्रयासों के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और प्रेरणा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है।

क्षेत्र को नशा मुक्त करने के लिए नगरी चौकी प्रभारी ने बांटे युवाओं को खेल किट

सामाजिक कार्यकर्ता रमन शर्मा ने कहा नगरी चौकी प्रभारी का एक सराहनीय कदम।

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

नगरी/कठुआ। शनिवार को कस्बा नगरी में नगरी चौकी प्रभारी रविंदर सिंह ने क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने के प्रयास से नगरी वार्ड 3 के स्थानीय युवाओं को खेल किट बंटी। इस मौके पर स्थानीय युवाओं ने नगरी चौकी प्रभारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, जिस तरह से नगरी चौकी प्रभारी क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वह सराहनीय कदम हैं।

इस मौके पर युवा सामा. जिक कार्यकर्ता रमन शर्मा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आगे भी चौकी प्रभारी इस तरह से कदम उठाएंगे और युवाओं को अपने साथ लेकर चलेंगे।

ताकि मिलकर हम क्षेत्र को नशा मुक्त कर सकें और युवाओं को खेल की ओर ले जा सकें।

जबकि रमन शर्मा ने कहा कि हम भी युवा साथियों के साथ मिलकर चौकी प्रभारी का पूरा साथ देंगे और इस क्षेत्र को नशा मुक्त करने का भी प्रयास करेंगे।

इस मौके पर रिंकू, साहिल, खली, बलविंदर, रिंकू, सुमित, दीपू, नारायण, निखिल,आयुष व अन्य युवा उपस्थित थे।

सद्गुरू श्री मधुपरमहंस जी महाराज ने आज मिश्रीवाला में अपने प्रवनचों की अमृतवर्षा से संगत को किया निहाल

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू। साहिब बंदगी के सद्गुरु श्री मधुपरमहंस जी महाराज ने आज मिश्रीवाला में अपने प्रवनचों की अमृतवर्षा से संगत को निहाल करते हुए कहा कि भक्ति सब गुणों की खानि है, लेकिन सत्संग से ही इसकी प्राप्ति होती है। हरेक इंसान धन कमाने में लगा है, क्योंकि वो जानता है कि धन से ही सारे काम हैं। भक्ति सभी गुणों को जन्म कैसे देती है और वो गुण हमें ईश्वर तक कैसे ले जाते हैं। हरेक इंसान काम कर रहा है। मन्तव्य एक है कि धन आए। सब चाहते हैं कि अच्छा आहार मिले। अच्छे आहार का आधार क्या है। पोष्टिक भोजन मिले। उसका माध्यम है धन। धन के लिए कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ। भक्ति से पार कैसे होगा।

ऊपर चढ़ने के लिए हमें एक सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। ये सद्गुण सीढ़ी है। कहने सुनने के लिए सभी कहते हैं कि हम अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी का मूल्यांकण उसकी क्रियाओं से होता है। जब ये सद्गुरु आ जायेंगे तो आपको ऊपर जाने के लिए सीढ़ी मिल गयी।

धर्मदास जी ने साहिब से पूछा कि मन ने बड़े बड़े ज्ञानियों को, ध्यानियों को भी लपेट लिया, फिर हम कैसे पार होंगे।

साहिब ने कहा कि पुरुष शक्ति से मन काबू में आयेगा। धर्मदास जी ने पूछा कि ये पुरुष शक्ति क्या है। बोला कि 16 शक्तियाँ हैं परम पुरुष की। जब आपको नाम मिलेगा तो ये शक्तियाँ खुद ब खुद आ जायेंगी। आप केवल भोजन करो, बाकी काम जठर खुद करेगा। भूख है एनर्जि की कमी। शरीर के चलने के लिए एनर्जि चाहिए। जो निखट्टू बैठा है, उसको भी भोजन चाहिए। क्योंकि सभी अंग काम कर रहे हैं। आदमी केवल भोजन करता है। एक सिस्टम बना है कि बाकी काम पेट खुद करता है। इस तरह आपने नाम सुमिरन करना है, बाकी सब सद्गुण, सब शक्तियाँ आपमें खुद आ जायेंगी।

ज्ञान, सत्य, संतोष, धीरज, विवेक, निर्भयता आदि ये 16 ताकतें आपमें आ जायेंगी। ये काम, क्रोध आदि से लड़ाई करते हैं और मन वश में हो जाता है।

आपके अन्दर सब चीजें भरी पड़ी हैं, पर नजर नहीं आ रही हैं। भक्ति उन सबको उत्पन्न करने वाली है। आपको बस सुमिरन करना है। मानव जीवन का अवसर गँवाना नहीं है। जब ये ताकतें आ जायेंगी तो विकार खुद ब खुद खत्म हो जायेंगे। निर्मोही हो जायेगा। मौत को याद रखोगे तो पाप करोगे ही नहीं।

मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त न्यायाधीशों को न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ताशी रबस्तान ने आज मुख्य न्यायाधीश न्यायालय कक्ष, जम्मू में न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल, न्यायमूर्ति राजेश सेखरी और न्यायमूर्ति मोहम्मद यूसुफ वानी, अति. रिक्त न्यायाधीशों को जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में जम्मू से न्यायमूर्ति संजीव कुमार, न्यायमूर्ति सिंधु शर्मा, न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल, न्यायमूर्ति संजय धर, न्यायमूर्ति पुनीत गुप्ता और न्यायमूर्ति मोहम्मद अकरम चौधरी शामिल हुए, जबकि श्रीनगर से न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन, न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल, न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी, न्यायमूर्ति राहुल भारती और न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काजमी ने ऑनलाइन भाग लिया।

शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही रजिस्ट्रार जनरल शहजाद अज़ीम ने संचालित की, जिन्होंने भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग (नियुक्ति प्रभाग) से प्राप्त अधिसूचना, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति के वारंट और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की सामग्री को पढ़ा।

एलजी सिन्हा लखनऊ में प्रसिद्ध लेखक श्रीलाल शुक्ल की जन्म शताब्दी समारोह में शामिल हुए

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में प्रसिद्ध लेखक श्रीलाल शुक्ल की जन्म शताब्दी समारोह में भाग लिया।

श्रीलाल शुक्ल को श्रद्धांजलि देते हुए, उपराज्यपाल ने श्रीलाल शुक्ल के जीवन और कालातीत कार्यों और ग्रामीण भारत के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की उनकी गहरी समझ पर प्रकाश डाला।

उपराज्यपाल ने कहा, श्रीलाल शुक्ल के ज्ञान की शक्ति, उनके विचार, उनकी कल्पना, उनका व्यंग्य न केवल हमारा मनोरंजन करता है बल्कि हमें आत्मनिर्भर गांवों और विकसित भारत के निर्माण के लिए मार्गदर्शन भी करता है।

"सैकड़ों वर्षों में एक बार, कुछ लेखकों को अस्तित्व द्वारा उपलब्ध ज्ञान प्राप्त होता है। श्रीलाल शुक्ल उनमें से एक थे। उनका लेखन वास्तव में पथ पर एक प्रकाश है। श्रीलाल शुक्ल के कार्यों में जीवन के रहस्य और रोजमर्रा की जिंदगी के अंतरंग अनुभव शामिल हैं। मेरा मानना छ्छ्छहै कि उनके अनुभव से

लथपथ उनके शब्द शाश्वत हैं। राग दरबारी, विशेष रूप से, हमारी चेतना में समा गया है, "उपराज्यपाल ने कहा।

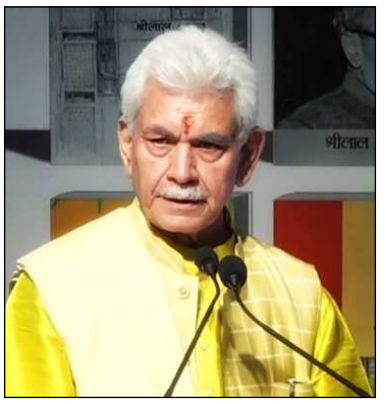

उपराज्यपाल ने समाज में सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करने के लिए श्रीलाल शुक्ल जैसे महान लेखकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

उपराज्यपाल ने कहा, "पुस्तकें शक्तिशाली आंतरिक आंखों की तरह होती हैं जो ज्ञान और बुद्धि की दुनिया की झलक प्रदान करती हैं। लेखक अपनी वर्णमाला के माध्यम से हमें सोचने और अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का अवसर देते हैं और ये लेखन संज्ञानात्मक अंतर्दृष्टि का स्रोत हैं।

"श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों और कहानियों ने उस अवधि के दौरान समाज को प्रबुद्ध करने का काम किया है और उनके विचार हमें हमारी विकासात्मक यात्रा में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की चेतावनी देते हैं और मेरा मानना छ्है कि उनके शब्द किसी भी अन्य प्रस्तुति से अधिक शक्तिशाली हैं"।

इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री; उत्तर प्रदेश जेपीएस राठौर; इफको के अध्यक्ष दिलीप संघानी और इफको के प्रबंध निदेशक डॉ यूएस अवस्थी ने भी बात की और श्रीलाल शुक्ल को श्रद्धांजलि दी।

बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी और अशोक पाठक ने श्रीलाल शुक्ल की प्रसिद्ध रचना श्राग दरबारीश का एक अंश सुनाया।

श्रीलाल शुक्ल की श्रद्धेय स्मृति में आयोजित एक प्रदर्शनी का भी उपराज्यपाल ने उद्घाटन किया।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने पूर्व विधायक की आत्महत्या पर शोक व्यक्त किया

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : जम्मू –कश्मीर विधानसभा ने गुरुवार को भाजपा नेता और गुरेज से पूर्व निर्दलीय विधायक फकीर मोहम्मद खान के निधन पर शोक व्यक्त किया।

भाजपा प्रवक्ता ने बताया कि खान (62) ने श्रीनगर के तुलसीबाग सरकारी आवास में खुद को गोली मार ली।

खान की आत्महत्या की खबर विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दी, जिसके बाद सदन ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए दो मिनट का मौन रखा। मुख्यमंत्री ने कहा, ष्मैं दुखद समाचार पर संवेदना व्यक्त करता हूं। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।ष्

जम्मू–कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर, विपक्ष के नेता सुनील शर्मा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य नजीर गुरेजी ने भी खान के निधन पर शोक व्यक्त किया।

27 विषयों में 594 लेक्चरर पद जेकेपीएससी को भेजे गए: इटू

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने आज सदन को सूचित किया कि जम्मू और कश्मीर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेष शिक्षकों की बाधाओं से निपटने के लिए 27 विषयों में 10+2 व्याख्याताओं के 594 पदों को भर्ती के लिए हाल ही में जम्मू–कश्मीर लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। मंत्री ने मेहराज मलिक द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही।

उन्होंने बताया कि डोडा जिले के विभिन्न उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विषयों में व्याख्याताओं के 367 पद रिक्त हैं। मंत्री ने आगे बताया कि शैक्षणिक सत्र 2024–25 के दौरान विशिष्ट विषयों को पढ़ाने के लिए डोडा जिले में अस्थायी आधार पर 140 क्लस्टर संसाधन समन्वयक (सीआरसी) नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से अनुदान की उपलब्धता के अधीन, समग्र शिक्षा के परामर्श से नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

उन्होंने कहा कि डोडा जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं की संख्या बढ़ाने के लिए, कम स्टाफ वाले स्कूलों की पहचान करने और इन स्कूलों में तैनाती के लिए अधिशेष स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए युक्तिकरण प्रक्रिया शुरू की गई है। इस बीच, उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने आज सदन को सूचित किया कि पहलगाम में होटल प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

मंत्री ने अल्ताफ अहमद वानी द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बात कही। मंत्री ने बताया कि होटलों के प्रबंधन को कॉलेजों में डिग्री प्रोग्राम के रूप में पेश नहीं किया जाता है, यह एक पेशेवर योग्यता है जिसके लिए एक अलग शैक्षणिक ढांचे की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान में उच्च शिक्षा विभाग के कॉलेजों में पेश किए जाने वाले चार साल के डिग्री प्रोग्राम से अलग है।

ऐशमुकाम में सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना के संबंध में, मंत्री ने सदन को सूचित किया कि पहलगाम–सिलिगाम/ ऐशमुकाम के नामकरण के साथ सरकारी डिग्री कॉलेज को फरवरी 2019 में मंजूरी दी गई थी उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने इस उद्देश्य के लिए अकद पार्क के सामने गांव अकद में जमीन का एक टुकड़ा भी चिन्हित कर लिया है। उन्होंने बताया कि कॉलेज के स्थान को लेकर सिलीगाम और ऐशमुकाम के दो गांवों के निवासियों के बीच विवाद के कारण मामला अदालत में पहुंचा और उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित कर दिया है।

एलजी सिन्हा ने पूर्व विधायक फकीर मोहम्मद खान के निधन पर शोक व्यक्त किया

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूर्व विधानसभा सदस्य फकीर मोहम्मद खान के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

गुरेज़ के विकास में फ़कीर मोहम्मद खान का योगदान बहुत बड़ा है और उन्होंने हज़ारों लोगों के जीवन को छुआ और बेहतर बनाया। इस बेहद दुखद अवसर पर, मैं उनके परिवार, दोस्तों और अनुयायियों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, उपराज्यपाल ने कहा।

पूर्व विधायक और भाजपा नेता ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

श्रीनगर : भाजपा नेता और जम्मू –कश्मीर के गुरेज से पूर्व निर्दलीय विधायक फकीर मोहम्मद खान ने गुरुवार को कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली।

उन्होंने बताया कि 62 वर्षीय खान ने तुलसीबाग सरकारी क्वार्टर के अंदर खुद को गोली मार ली। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि पूर्व विधायक की मौत आत्महत्या के कारण हुई है।

खान ने यह कदम क्यों उठाया, इसका तत्काल पता नहीं चल पाया है। 1996 में जम्मू–कश्मीर विधानसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने गए खान 2020 में भाजपा में शामिल हुए थे और पिछले साल पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

आवश्यक एनओसी प्राप्त करने के बाद ही स्टोन क्रशर स्थापित किए जाएं : उपमुख्यमंत्री

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने आज कहा कि स्टोन क्रशर/हॉट एंड वेट मिक्स प्लांट संबंधित विभागों से अना. पत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के बाद ही स्थापित किए जाते हैं।

मंत्री शेख खुर्शीद अहमद द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लघु खनिज आधारित इकाइयों को सुव्यवस्थित करने के लिए उन्हें जम्मू –कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त करनी होगी और भूमि के शीर्षक सत्यापन के संबंध में संबंधित जिले के उपायुक्त से एनओसी प्राप्त करना होगा।

बी–ए–मैदान क्रालगुंड काजियाबाद लंगेट में आंशिक रूप से कार्यात्मक क्रशर की स्थापना के बारे में, उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिलमैदान गांव, रसरीपोरा लारिगनपोरा, तहसील काजियाबाद में सर्वेक्षण संख्या 33 मिनट, 35 मिनट के तहत 05 कनाल भूमि का एक टुकड़ा अस्थायी आधार पर 30 महीने की अवधि के लिए बैचिंग प्लांट, बिटुमेन प्लांट और मुख्य स्टोर की स्थापना के लिए चिह्नित किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे आरकेसीटीसी सड़क को पूरा करने की आवश्यकताएं पूरी होंगी, जो कि डव्ल्ब् द्वारा एक राष्ट्रीय प्राथमिकता परियोजना है। उन्होंने बताया कि डिप्टी कमिश्नर, कुपवाड़ा ने सूचित किया है कि मामले में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना बाकी है क्योंकि विभिन्न दस्तावेज अभी भी प्रक्रिया में हैं। उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 2021 के एसओ 60 दिनांकरू 23.02.2021 के अनुसार स्टोन क्रशर इकाई की स्थापना के लिए भूविज्ञान और खनन विभाग से किसी एनओसी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों से लीज एग्रीमेंट, पर्यावरण मंजूरी और एनओसी प्रक्रियाधीन है और स्टोन क्रशरों की कार्यशीलता या गैर–कार्यक्षमता संबंधित जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आती है।

इस बीच, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने सदन को सूचित किया कि 16.20 किलोमीटर संग्रामा–सोपोर–सागीपोरा सड़क के उन्नयन के लिए 1811.54 लाख रुपये की राशि के लिए एक व्यापक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है, जो नाबार्ड आरआईडीएफ के तहत मंजूरी के लिए विच. राधीन है।

बुधल में हुई मौतों की जांच जारी है–सकीना इत्तू

सभी 17 मृतकों के नमूनों में आंतरिक अंग में क्लोरफेनेपायर पाया गया

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने कहा कि राजौरी के बुधल क्षेत्र में बीमारी और मौतों का कारण बैक्टीरिया या वायरल मूल की कोई संक्रामक बीमारी नहीं है।

मंत्री ने जावेद इकबाल चौधरी द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि नैदानिक रिपोर्ट, प्रयोगशाला जांच और पर्यावरण नमूनों से संकेत मिलता है कि ये घटनाएं बैक्टीरिया या वायरल मूल की किसी संक्रामक बीमारी के कारण नहीं हैं, इसके बजाय, पीजीएमआईईआर चंडीगढ़ द्वारा पता लगाने से एल्यूमीनियम और कैडमियम की उपस्थिति का पता चलता है।

सीएसआईआर– आईआईटीआर, लखनऊ ने एल्डीकार्ब सल्फेट और एसिटामिप्राइड डाइएथिल डाइथियोकार्बामेट, क्लोरफेनेपायर पाया। डीआरडीई–डीआरडीओ ग्वालियर ने सत्तू और मक्के की रोटी के नमूनों से क्लोरफेनेपायर, एब्रिन पाया।

मंत्री ने कहा कि एनएफएल, एफएसएसएआई गाजियाबाद ने खाद्य नमूनों से क्लोरफेनेपायर और क्लोरपाइरोफॉस पाया। सीएफएसएल, चंडीगढ़ ने सभी 17 मृतकों के नमूनों में आंतरिक अंग में क्लोरफेनेपायर पाया।

मंत्री ने सदन को बताया कि जीएमसी राजौरी में भर्ती मरीजों की कुल संख्या 64 है, इनमें से 41 को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है और 17 मरीजों को जीएमसी जम्मू और 01 मरीज को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है।

उन्होंने कहा कि जीएमसी राजौरी में 06 मरीजों की मौत हुई है जबकि जीएमसी और एसएमजीएस अस्पताल, जम्मू में 11 मरीजों की मौत हुई है।

मंत्री ने कहा कि बुधल क्षेत्र के मरीजों के लिए एक मानक उपचार नीति और डिस्चार्ज प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसे एम्स नई दिल्ली/पीजीआई चंडीगढ़ की विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाया गया है।

इन टीमों द्वारा निर्धारित सभी एसओपी को अस्पताल में मरीजों के रहने के दौरान और साथ ही डिस्चार्ज और फॉलो–अप के समय अपनाया जाता है।

जीएमसी जम्मू में, मंत्री ने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जम्मू में मरीजों के संबंध में जीएमसीएच राजौरी से रेफर किए जाने के बाद जीएमसीएच जम्मू में भर्ती सभी तीन मरीजों के लिए उचित एसआ.`पी और प्रोटोकॉल का पालन किया गया था। उन्होंने कहा कि, 2 मरीजों को अलग से आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था, 1 मरीज को पीजीआई चंडीगढ़ से सर कर्नल चोपड़ा नर्सिंग होम में अलग कमरे में स्थानांतरित किया गया था।

इसके अलावा, एसएमजीएस अस्पताल जम्मू द्वारा अपनाई गई एसओपी कि वार्ड 19 को बुधल राजौरी से प्राप्त मरीजों के लिए आइसोलेशन रूम में परिवर्तित कर दिया गया।

गांव बुधल, जिला राजौरी के मृतक परिवार के सदस्यों को 1 लाख रुपये और राजौरी के डिप्टी कमिश्नर द्वारा लाभार्थियों को रेड क्रॉस फंड से 50,000 रुपये दिए गए।

पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने सदन को बताया कि जांच के लिए 3500 लोगों के नमूने लिए गए हैं और जांच चल रही है।

टोनी ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी पर चिंता जताई

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सुचेतगढ़ के डीडीसी तरनजीत सिंह टोनी ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में कर्मचारियों की भारी कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्र सीधे तौर पर लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। उन्होंने चिकित्सा और शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए व्यापक सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

आज यहां बेरोजगार युवाओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें डॉक्टरों के लिए एक मजबूत पर्यवेक्षण तंत्र होना चाहिए ताकि इष्टतम उत्पादकता सुनिश्चित की जा सके।

उन्होंने जोर देकर कहा, ष्हमें स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को इस तरह से चौनलाइज़ करने की आवश्यकता है जिससे अधिकतम लोगों को लाभ मिले, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में जहां चिकित्सा सहायता की कमी है।ष उन्होंने आगे कहा कि जम्मू और कश्मीर के हर कोने तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे, दवाओं की समय पर उपलब्धता और चिकित्सा पेशेवरों की तैनाती में वृद्धि की जानी चाहिए। इसी तरह, शिक्षा क्षेत्र में चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए टोनी ने भर्ती की तदर्थ प्रणाली को समाप्त करके शिक्षा को प्राथमिकता देने की सख्त जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि कई तदर्थ व्याख्याता बिना नियमित किए तीन साल से अधिक समय से सेवा दे रहे हैं, जो उनके योगदान और प्रतिबद्धता के साथ घोर अन्याय है। उन्होंने मांग की कि सभी नियुक्त व्याख्याताओं को तुरंत स्थायी किया जाए, ताकि शिक्षा प्रणाली में स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

भद्रवाह विधानसभा क्षेत्र में 683 शिक्षण एवं गैर–शिक्षण पद रिक्त–शिक्षा मंत्री

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने विधानसभा में दलीप सिंह परिहार द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि भद्रवाह विधानसभा क्षेत्र में 683 शिक्षण एवं गैर–शिक्षण पद रिक्त हैं। इन पदों में प्रिंसिपल, हेडमास्टर, मास्टर, शिक्षक और गैर–शिक्षण कर्मचारी शामिल हैं।

मंत्री ने कहा कि शिक्षकों के पदों पर रोक के कारण पिछले 6 वर्षों से विभाग में शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं हो पाई है, जिससे स्कूलों में शिक्षण कर्मचारियों की कमी हो गई है।

हालांकि, स्कूल शिक्षा विभाग स्कूलों में शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारियों को सुव्यवस्थित करने और छात्र–शिक्षक अनुपात को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहा है। उन्होंने कहा कि युक्तिकरण तंत्र के माध्यम से कम कर्मचारियों वाले स्कूलों और अधिशेष शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारियों की पहचान की जाती है और बाद में जहां भी आवश्यकता होती है, उन्हें तैनात किया जाता है। इसके अलावा, विभाग क्लस्टर संसाधन समन्वयकों को विषय विशेष शिक्षकों के रूप में उपयोग कर रहा है।

उन्होंने कहा कि विभाग पदोन्नति के माध्यम से शिक्षण और गैर–शिक्षण के विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों को भर रहा है।

भद्रवाह निर्वाचन क्षेत्र के अधिकांश स्कूलों में बुनियादी ढांचा मौजूद है, हालांकि मौजूदा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और निर्वाचन क्षेत्र के स्कूलों में आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए स्कूलों में बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए जिला कैपेक्स, यूटी कैपेक्स और समग्र शिक्षा योजना के तहत 155 कार्य निर्माणाधीन हैं। विभाग में रिक्तियों को भरने के लिए 504 पदों को बोर्ड को भेजा गया है।

भाजपा विधायक ने पक्षपात का आरोप लगाते हुए जम्मू–कश्मीर विधानसभा से वॉकआउट किया

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : बजट सत्र के दौरान बोलने के लिए समय न देने और सदन की कार्यवाही में उनके प्रश्नों को शामिल न करने का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक आरएस पठानिया ने मंगलवार को जम्मू–कश्मीर विधानसभा से बहिर्गमन किया।

पठानिया ने प्रश्नकाल के दौरान दिन के कामकाज में सूचीबद्ध अपना प्रश्न उठाने का प्रयास किया।

हालांकि, स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने उन्हें यह कहते हुए अपना प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी कि उन्होंने पठानिया का नाम पहले ही पुकारा था, लेकिन वे सदन में अनुपस्थित थे।

विधायक ने खराब यातायात प्रबंधन का हवाला देते हुए बताया कि वे ट्रैफिक जाम के कारण देरी से आए थे।

उन्होंने स्पीकर और विधानसभा सचिवालय पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया, क्योंकि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया और उनके सवालों को सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया।

स्पीकर के फैसले से नाराज होकर उन्होंने जम्मू–कश्मीर विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। पठानिया ने

विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से कहा, ष्सदन के कामकाज के अनुसार, प्रत्येक विधायक को तारांकित और अतारांकित दोनों प्रारूपों में 10–10 सवाल उठाने की अनुमति है। इनमें से मेरे केवल एक सवाल को सदन की कार्यवाही में शामिल किया गया। 19 सवाल लंबित हैं और सत्र समाप्त होने में केवल सात दिन बचे हैं।ष

उन्होंने कहा कि उन्होंने स्पीकर और विधानसभा सचिवालय के पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ विरोध जताया।

जम्मू में सीएम अब्दुल्ला के आवास तक पीएचई दैनिक वेतनभोगियों के विरोध मार्च को पुलिस ने विफल किया

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू: पुलिस ने शुक्रवार को लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) विभाग के दैनिक वेतनभोगियों द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर निकाले जा रहे विरोध मार्च को विफल कर दिया और उन्हें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास की ओर बढ़ने से रोकने के लिए उन पर हल्का लाठीचार्ज किया।

जल शक्ति विभाग के दैनिक वेतनभोगियों ने 72 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है। उमर अब्दुल्ला होश में आओ – होश में आओ जैसे नारे लगाते हुए, पीएचई कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी मुख्यमंत्री के आवास की ओर मार्च कर रहे थे।

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपने नियमितीकरण और लंबित वेतन जारी करने में सरकार की देरी के खिलाफ विरोध कर रहे थे। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, जिनमें से कुछ को प्रदर्शनकारियों ने पार कर लिया।

इस पर पुलिस को हल्के लाठीचार्ज का इस्तेमाल करना पड़ा।

बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को शहीदी चौक से आगे बढ़ने से रोक दिया। दिहाड़ी मजदूरों के नेताओं ने चुनाव से पहले किए गए वादों के बावजूद नियमित.ीकरण और वेतन जारी करने के उनके लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने में विफल रहने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की आला.ोचना की। दशकों से, कई सरकारों ने हमें धोखा दिया है। यह एक और धोखा है। उन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया।

सरकार की समिति केवल एक विलंब करने की रणनीति है। इस तरह के लॉलीपॉप हमारे परिवारों का भरण–पोषण नहीं कर सकते, एक प्रदर्शनकारी नेता ने संवाददाताओं से कहा।

मुख्यमंत्री अब्दुल्ला पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता गरीब दिहाड़ी मजदूरों की अनदेखी करते हैं, लेकिन विधायकों के वेतन और उनके निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष को 4 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की पहल कर सकते हैं।

प्रदर्शनकारियों ने मांग की, ष्विधायकों को अपना वेतन हमारे विभाग के वेतन खाते में स्थानांतरित करना चाहिए, जहां से हमें अपना वेतन मिलता है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा में उनके द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन हमारे लिए मायने नहीं रखता। जम्मू–कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में दिहाड़ी मजदूरों के नियमित.ीकरण से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए बुधवार को छह सदस्यीय समिति का गठन किया।

इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री ने जम्मू–कश्मीर में दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए एक समिति की घोषणा की और कहा कि अगले बजट सत्र में प्रस्तुति के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा।

दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पैनल गठितः सीएम उमर अब्दुल्ला

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : जम्मू –कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक वेतनभोगियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर विचार के लिए एक समिति गठित की गई है, जो छह महीने में सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जम्मू–कश्मीर में सरकारी सेवाओं में रिक्त पदों को भरने के लिए तेजी से भर्ती सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा में भाजपा विधायक सतीश शर्मा के एक सवाल का जवाब देते हुए अब्दुल्ला ने कहा, ष्पिछली बार विधानसभा में एक समिति की घोषणा की गई थी, और इसके गठन के लिए एक औपचारिक आदेश जारी किया गया था। इस मुद्दे की जांच के लिए मुख्य सचिव के तहत समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैनल को

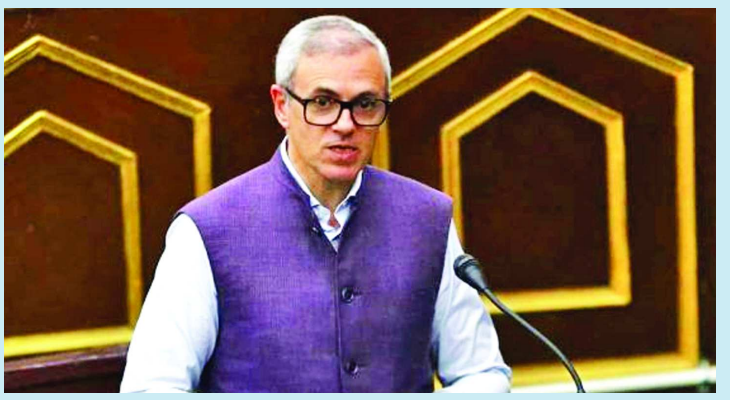

मामले का आकलन करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है और सिफारिशें मिलने के बाद सरकार उसके अनुसार काम करेगी।

जेके सरकार ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश में दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया।

फास्ट–ट्रैक भर्ती के मुद्दे पर अब्दुल्ला ने रिक्तियों को कुशलतापूर्वक भरने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

ष्जेके सरकार ने पिछले दो वर्षों में 15,000 से अधिक रिक्तियों को भरते हुए अपनी भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी लाई है। पिछले दो वर्षों में 13,466 गैर–राजपत्रित रिक्तियों को जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड को भेजा गया था, जिनमें से 9,351 चयन पूरे हो चुके हैं।

अब्दुल्ला ने कहा, इसी तरह, जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग को भेजी गई 2,390 राजपत्रित रिक्तियों में से 2,175 का चयन किया गया है।ष

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भर्ती को और अधिक सुव्यवस्थित करने के प्रयास चल रहे हैं।

ष्हमने वित्त विभाग द्वारा वर्तमान में समीक्षाधीन 10,757 मल्टी–टास्क सर्विस रिक्तियों की पहचान की है। इन पदों को जल्द ही भर्ती एजेंसियों को भेजा जाएगा। इसके अलावा, 6,000 रिक्तियां रेफरल के लिए तैयार हैं और जल्द ही भर्ती के लिए भेजी जाएंगी," उन्होंने कहा।

भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार ने पे लेवल 5 (29,200–92,300 रुपये) तक के सभी पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिया था।

14 फरवरी के एक हालिया आदेश ने जूनियर इंजीनियरों और नायब तहसीलदारों सहित लेवल 6 के पदों के लिए साक्षात्कार की आवश्यकता को हटा दिया है।

भारतीय अधिकारी पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

नई दिल्लीः पाकिस्तानी उच्चायुक्त साद अहमद वराइच ने कहा है कि आपसी समझ बढ़ाने, साझा चिंताओं को दूर करने और कश्मीर मुद्दे सहित ष्दीर्घकालिक विवादोंष को हल करके पाकिस्तान–भारत संबंधों में एक ष्नई सुबहष आ सकती है।पाकिस्तानी राज.दूत की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक पॉडकास्ट में दिए गए उस बयान के कुछ दिनों बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ शांति को बढ़ावा देने के हर प्रयास को शत्रुता और विश्वासघात के साथ मिला है और उन्हें उम्मीद है कि द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए इस्लामाबाद में नेतृत्व को समझदारी से काम लेना होगा।

वराइच ने यह टिप्पणी गुरुवार रात देश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पाकिस्तानी उच्चायोग द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में की। इस कार्यक्रम में भारतीय पक्ष से कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान ने इस स्वागत समारोह के लिए भारतीय अधिकारियों को आमंत्रित किया था या नहीं।

भारत यह कहता रहा है कि वह पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी संबंध चाहता है, जबकि इस बात पर जोर देता रहा है कि इस तरह के जुड़ाव के लिए आतंक और शत्रुता से मुक्त वातावरण बनाने की जिम्मेदारी इस्लामाबाद की है।

नई दिल्ली इस बात पर भी जोर दे रही है कि पूरा जम्मू–कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान ने केंद्र शासित प्रदेश के कुछ हिस्सों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है।

पाकिस्तानी राजनयिक ने जोर देकर कहा कि इस्लामाबाद ने ष्संप्रभु समानता, आपसी सम्मान और शांतिपूर्ण सह–अस्तित्वष के सिद्धांतों के आधार पर अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का लगातार प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस शिक्षाप्रद दृष्टिकोण ने भारत के साथ शांतिपूर्ण संबंधों की हमारी खोज को भी निर्देशित किया है।

वराइच ने रेखांकित किया, ष्दक्षिण एशिया – हमारा साझा घर – को स्थिर शांति, समान सुरक्षा और साझा समृद्धि के साथ आगे बढ़ना चाहिए।ष

इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने एक रचनात्मक भावना की आवश्यकता पर बल दिया, जो साझा समाधानों की दिशा में सहयोगी प्रयासों को प्राथमिकता दे और जबरन परिणाम थोपने की कोशिश न करे।

भारत-पाक इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं : पूर्व पाक विदेश मंत्री

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

लाहौरः पाकिस्तान के पूर्व विद.ेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी ने मौजूदा दौर को भारत और पाकिस्तान के बीच इतिहास के सबसे खराब दौरों में से एक बताया है, वास्तविक युद्ध के समय को छोड़कर, लेकिन कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में अचानक सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं।

इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कनेक्टिविटी (प्च्।ब्) द्वारा गुरुवार को यहां आयोजित श्पाकिस्तान–भारत संबंध – वर्तमान स्थिति और आगे का रास्ताश नामक कार्यक्रम में बोलते हुए कसूरी ने कहा कि दोनों देशों के लिए अपने लंबित मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत ही एकमात्र समाधान है।

वर्तमान समय को दोनों देशों के बीच इतिहास के सबसे बुरे समय में से एक बताते हुए, वास्तविक युद्ध के समय को छोड़कर, कसूरी ने कहा कि युद्धों के बाद भी, पाकिस्तान और भारत शांति प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए जल्दी से बातचीत की मेज पर आए।

सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली आप प्रमुख, मेहराज मलिक को जम्मू-कश्मीर इकाई का प्रमुख नियुक्त किया

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

नई दिल्लीः पिछले महीने हुए विधानसभा चुनावों में अपने गृह क्षेत्र दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को एक बड़े संगठनात्मक फेरबदल की घोषणा करते हुए पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज को अपनी दिल्ली इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया और मेहराज मलिक को पार्टी की जम्मू–कश्मीर इकाई का नया प्रमुख बनाया गया है। भारद्वाज ने गोपाल राय की जगह ली, जबकि सिसोदिया ने पंजाब का प्रभार संभाला, जो देश का एकमात्र राज्य है जहां आम आदमी पार्टी (आप) वर्तमान में सत्ता में है।

पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के आवास पर आप की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की बैठक के दौरान ये निर्णय लिए गए। बदलावों की घोषणा करते हुए आप महासचिव (संगठन) संदीप पाठक ने कहा कि गोपाल राय को गुजरात का प्रभार दिया गया है, जहां पार्टी अपना आधार बढ़ाने का लक्ष्य बना रही है। राज्यसभा सांसद पाठक को आप की छत्तीसगढ़ इकाई का प्रभारी बनाया गया है, जबकि पंकज गुप्ता पार्टी की गोवा इकाई का नेतृत्व करेंगे।

मेहराज मलिक को पार्टी की जम्मू–कश्मीर इकाई का नया प्रमुख बनाया गया है। पाठक ने

कहा कि बैठक में दिल्ली में भाजपा द्वारा किए गए "अधूरे" वादों पर भी चर्चा हुई, जिसमें 2,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता और महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देना शामिल है।

बिजबिहाड़ा–श्रीगुफवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में नहरों की वहन क्षमता बढ़ाने के लिए 37.00 करोड़ रूपये की डीपीआर तैयार–जावेद राणा

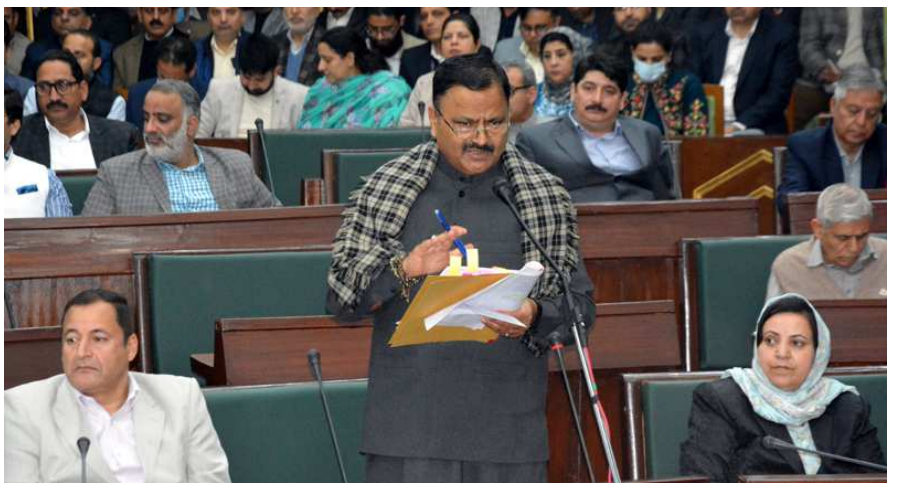

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने बशीर अहमद वीरी द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सदन को सूचित किया कि बिजबिहाड़ा– श्रीगुफवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र की विभिन्न नहरों की वहन क्षमता बढ़ाने के लिए 37.00 करोड़ रुपये की राशि के लिए डीपीआर तैयार की गई है, जो नाबार्ड 2025–26 की परियोजना का हिस्सा होगी।

मंत्री ने कहा कि सिंचाई नहरों पर अतिक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा नियमित अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024–25 में करीब 658 अतिक्रमण हटाए गए, जिसमें 300.02 कनाल सरकारी भूमि वापस प्राप्त की गई। नहरों के कुछ हिस्से ऐसे हैं, जिनके किनारों पर अतिक्रमण है। हालांकि, मुख्य जलमार्ग किसी भी अतिक्रमण से मुक्त है, जिससे प्रवाह में बाधा नहीं आएगी। कुछ हिस्सों में रिसाव वाले स्थानों और गाद के जमाव को छोड़कर, कोई बड़ी बाधा नहीं है, जिससे पर्याप्त सिंचाई जल की आपूर्ति में बाधा आए। मंत्री ने कहा कि गाद हटाना रखरखाव का काम है, जो नहरों में नियमित आधार पर किया जाता है, आमतौर पर हर सिंचाई सीजन के बाद, चरणबद्ध अनुबंधों के साथ–साथ अभिसरण मोड के माध्यम से।

नहरों की सफाई के संबंध में मंत्री ने बताया कि एमएंडआर अनुदान के तहत 2024–25 के दौरान 5.82 लाख रुपये की लागत से 17 किलोमीटर बिजबिहाड़ा–श्रीगुफवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र की नहरों की सफाई की गई है।

माहौर में 50 बिस्तरों वाले जीएंडबी छात्रावास का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है–जनजातीय कार्य मंत्री

एजेंसी

जम्मू : जनजातीय कार्य मंत्री जावेद अहमद राणा ने विधानसभा में खुर्शीद अहमद द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि माहौर में 168.25 लाख रुपये की लागत से बनने वाले 50 बिस्तरों वाले एसटी छात्रावास का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

मंत्री ने सदन को बताया कि वर्ष 2009–10 में 96.13 लाख रुपये की लागत से कार्य शुरू किया गया था, जिसे वर्ष 2017–18 में संशो. धित कर 168.25 लाख रुपये कर दिया गया और यह कार्य वर्ष 2018–19 तक जारी रहा। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान चारदीवारी और अन्य संबद्ध कार्यों जैसे शेष कार्य भी पूरे कर लिए गए हैं और इसमें 50 छात्रों के रहने की क्षमता है।

हालांकि, मंत्री ने कहा कि चूंकि इमारत काफी समय से सुरक्षा बलों के कब्जे में है, इसलिए इसे उपयोग के लिए रहने योग्य बनाने के लिए कुछ और मरम्मत और नवीनीकरण की आवश्यकता है। भूमि मालिक को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और देय मुआवजा राशि निर्धारित करने के लिए अधिग्रहण की कार्यवाही पहले ही शुरू हो चुकी है और इस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

उन्होंने आगे बताया कि यूटी कैपेक्स बजट 2023–24 के तहत स्वीकृत 40.00 लाख रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है, जो कलेक्टर भूमि अधिग्रहण माहौर के पास उपलब्ध है।

हालांकि, एसडीएम, माहौर ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत भूमि मालिकों को मुआवजे के भुगतान के लिए कुल 1.30 करोड़ रुपये, जो लगभग 1.70 करोड़ रुपये है, की अतिरिक्त धनराशि की मांग की है।

मंत्री ने कहा कि उक्त छात्रावास को चालू करने के लिए अभी तक कोई स्टाफ स्वीकृत नहीं किया गया है, हालांकि, मामले पर सक्रियता से विचार किया

रविंदर रैना, चौधरी जुल्फकार अली ने काजीगुंड में गुज्जर बकरवाल पीड़ित परिवारों से मुलाकात की

जम्मू लद्दाख विजन ब्यूरो

जम्मू : जम्मू–कश्मीर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रविंदर रैना ने चौधरी जुल्फकार अली के साथ काजीगुंड में गुज्जर बकरवाल पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष कुलगाम फारूक राथर, वरिष्ठ नेता आबिद हुसैन, जिला अध्यक्ष अनंतनाग राकेश कौल, पिंका मलिक और पार्टी के कई अन्य नेता भी उपस्थित थे।

रविंदर रैना ने कहा कि दुर्भाग्य से 3 युवक काफी समय से लापता थे, जिनमें से 2 युवकों के शव बरामद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन अभी भी घटना के बारे में सटीक जानकारी नहीं जुटा पाया है और तीसरा लापता व्यक्ति कौन है।

उन्होंने कहा कि शौकत बजाड़ और रियाज अहमद के शव बरामद हो गए हैं, लेकिन तीसरा व्यक्ति मुख्तार अहमद अभी भी लापता है।

रविंदर रैना ने पीड़ित परि. जनों से बात करते हुए पीड़ित परिवारों को न्याय और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

उन्होंने कहा कि एनसी सरकार को तीनों लोगों के लापता होने की जांच में तेजी लाने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा देश और समाज का भविष्य हैं और प्रशासन को पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए जरूरत पड़ने पर अधिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि वे इस मामले को उचित प्राधिका. रियों के समक्ष उठाएंगे ताकि मजबूत तकनीकी और जांच उपाय सुनिश्चित किए जा सकें।

चौधरी जुल्फकार अली ने प्रशासन से कानून प्रवर्तन एजेंसियों, स्थानीय अधिकारियों और जनता के बीच समन्वय स्थापित करते हुए व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया।

उन्होंने परिवारों को आश्वा. सन दिया कि उन्हें जल्द ही राहत प्रदान की जाएगी।

जम्मू-कश्मीर में निवेश के लिए गैर-स्थानीय लोगों को 2 हजार कनाल से अधिक भूमि आवंटित की गई : सरकार

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : जम्मू –कश्मीर सरकार ने बुधवार को कहा कि जम्मू–कश्मीर में निवेश के लिए गैर–स्थानीय लोगों को 2000 कनाल से अधिक भूमि आवंटित की गई है।

पीडीपी विधायक वहीद–उल–रहमान पारा द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए, जिसमें पिछले दो वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में निवेश के लिए गैर–स्थानीय लोगों को प्रदान की गई भूमि का विवरण मांगा गया था, सरकार ने एक लिखित उत्तर में कहा कि 1 जनवरी, 2023 से 12 दिसंबर, 2024 की अवधि के दौरान पिछले दो वर्षों के दौरान सिडको औद्योगिक एस्टेट में गैर–निवासियों को 2093 कनाल भूमि आवंटित की गई है। विवरण साझा करते हुए, सरकार ने कहा कि कठुआ में, भगथली–। में मेसर्स आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड को 275 कनाल भूमि, मेसर्स ग्रेव एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट– ।) को 222 कनाल और मेसर्स ग्रेव एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट– II) को 424 कनाल भूमि आवंटित की गई है।

भागथली–प्प में 201 कनाल भूमि मेसर्स एडवांस फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को, 201 कनाल भूमि मेसर्स ग्रीनक्वेस्ट अलू फोइल्स प्राइवेट लिमिटेड को, 201 कनाल भूमि मेसर्स हल्दीराम स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को, 209 कनाल भूमि मेसर्स सिंटेक्स एडवांस प्लास्टिक लिमिटेड को तथा 206 कनाल भूमि मेसर्स सीलोन बेवरेज कैन प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित की गई है।

इस बीच श्रीनगर में मेडिसिटी सेम्पोरस (जीआर) में 30 कनाल भूमि मेसर्स मेगना वेल्स बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड (ईएमएएआर ग्रुप–यूएई) को तथा 100 कनाल भूमि मेसर्स मेगना वेल्स बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (ईएमएएआर ग्रुप यूएई) को आवंटित की गई

है।

प्रदर्शनी ग्राउंड जम्मू में 24 कनाल भूमि मेसर्स मैग्ना वेल्स बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित की गई है।

पिछले दो वर्षों के दौरान कई औद्योगिक एस्टेट, अन्य सार्वजनिक और निजी प्राधिकरणों को हस्तांतरित भूमि के कुल क्षेत्रफल के विवरण के बारे में एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, सरकार ने कहा, जम्मू संभाग में 6014 कनाल और 10 मरला तथा कश्मीर संभाग में 5532 कनाल और 19 मरला आवंटित किया गया है।

सरकार ने यह भी उत्तर दिया कि पिछले दो वर्षों के दौरान औद्योगिक एस्टेट (सार्वजनिक उद्देश्य) की स्थापना के अलावा सार्वजनिक और निजी प्राधिकरणों को कोई भूमि क्षेत्र या पैच हस्तांतरित नहीं किया गया है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में चार्टर्ड उड़ानों पर खर्च हुए करोड़ों रूपये को लेकर हंगामा, विधायकों ने की जांच की मांग

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : जम्मू–कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को हंगामा हुआ, जब एक निर्दलीय विधायक द्वारा केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में चार्टर्ड उड़ानों और अन्य खर्चों पर करोड़ों रुपये खर्च करने की जांच की मांग के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप–प्रत्यारोप का दौर चला।

सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और कांग्रेस के सदस्यों ने प्रशासन द्वारा क्षेत्र में ऐसे मेहमानों पर करोड़ों रुपये खर्च करने की जांच के लिए एक सदन समिति के गठन की मांग की।

विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के अनुदानों पर बोलते हुए, शोपियां के विधायक शब्बीर अहमद कुल्ले ने चार्टर्ड उड़ानों के इस्तेमाल और जेके में मेहमानों पर 35 करोड़ रुपये की अधिक राशि खर्च करने का मुद्दा उठाया।

कुल्ले ने कहा, ष्मुझे इस पर इतने बड़े खर्च के बारे में कट मोशन में जवाब मिला है। इसकी जांच की जरूरत है।ष

जी–20 सहित जेके में विभिन्न व्यक्तियों पर 35 करोड़ रुपये खर्च करने की ओर इशारा करते हुए, विधायक ने कहा, कुल्ले ने कहा, ष्हमें जांच करनी चाहिए कि सरकारी खजाने से इतना पैसा कैसे खर्च किया गया। सदन की समिति गठित

कर जांच की मांग करने में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने उनका समर्थन किया।

नेकां सदस्य जावेद बेघ ने कहा, ष्हम चाहते हैं कि इसकी जांच के लिए सदन की समिति गठित की जाए।ष कांग्रेस और निर्दलीयों में से कुछ नेकां के सभी सदस्य सदन की समिति द्वारा जांच की मांग करते हुए अपनी सीटों से खड़े हो गए।

हालांकि, भाजपा के सदस्य भी दूसरी तरफ खड़े थे, उन्होंने बताया कि यह जी20 मेहमानों के लिए था और अन्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थे।

भाजपा के बलवंत मनकोटिया ने कहा, ष्मुख्यमंत्री के पास पूरा अधिक.ार है क्योंकि यह उनका विभाग है। कृपया दीर्घाओं को संबोधित न करें। हमें 2009 से निधि के खर्च की जांच करने दें, जब आपकी सरकार थी,ष उन्होंने कहा।

इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध किया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ समय के लिए मौखिक द्वंद्व और शोरगुल हुआ।

नेकां विधायक तनवीर सादिक ने सदन की समिति के गठन की मांग की क्योंकि राज्य के खजाने से कुछ लोगों पर भारी खर्च किया गया था। ष्इसे किसने मंजूरी दी है? उन्होंने कहा, ष्ये कौन लोग हैं जिनके लिए इसका इस्तेमाल किया गया?ष

कांग्रेस सदस्य निजामुद्दीन भट ने कहा, ष्यह मुद्दा जनता के पैसे से जुड़ा है, जो विधानसभा के अधिकार क्षेत्र में आता है। सदस्य ने गंभीर आरोप लगाए हैं।

उन्होंने कहा, ष्इसकी सत्यता का पता लगाने के लिए इसकी जांच की जानी चाहिए। सदन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए जांच के लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए।ष

भाजपा सदस्यों ने उनका जवाब देते हुए कहा कि सदस्य को अपने आरोपों की पुष्टि करनी चाहिए क्योंकि सदन का इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने 2008 से अब तक खर्च किए गए धन की जांच की भी मांग की।

भाजपा सदस्य पवन गुप्ता ने कहा, ष्सदस्य को सबूतों के साथ इसे पुष्ट करना चाहिए। यह केवल आरोपों पर आधारित नहीं होना चाहिए।ष

स्वतंत्र सदस्य शबीर अहमद और मेहराज मलिक सदन के वेल में चले गए और अध्यक्ष को कुछ कागजात सौंपे, कहा कि ये सबूत हैं।

समिति के गठन का विरोध करते हुए, पीडीपी सदस्य फैयाज मीर ने कहा कि यह सदन समिति के गठन के लिए सही मुद्दा है क्योंकि यह राज्य के मेहमानों से संबंधित है, जिसमें जी–20 के मेहमान भी शामिल हैं।

आरोपों पर शोरगुल और हंगामे के बीच, अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने हस्तक्षेप किया और कहा कि अनुदान पर चर्चा के दौरान कुछ मुद्दे सामने आए हैं।

उन्होंने कहा, ष्मुख्यमंत्री अभी भी यहां हैं। वह अनुदान पर अपने जवाब के दौरान उन्हें संबोधित करेंगे। चिंताओं का समाधान किया जाएगा।ष

उन्होंने सदन के सदस्यों से शांति बनाए रखने का भी आह्वान किया।

कुछ राज्यों के साथ रॉयल्टी, कर बकाया की वसूली के मुद्दे को सुलझाने के प्रयास जारी: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

नई दिल्ली : केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह अपने और कई खनिज संपन्न राज्यों के बीच खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर रॉयल्टी और कर बकाया की वसूली के मुद्दे को सुलझाने का प्रयास कर रहा है। इस बीच, शीर्ष अदालत ने झारखंड जैसे कई खनिज संपन्न राज्यों की बाद की याचिकाओं पर सुनवाई 24 अप्रैल तक के लिए टाल दी, जिसमें केंद्र और खनन फर्मों से हजारों करोड़ रुपये के खनिज अधिकारों और खनिज युक्त भूमि पर रॉयल्टी और कर बकाया वसूलने की मांग की गई थी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस उज्जल भुइयां की तीन–न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने कहा कि वह कई खनिज संपन्न राज्यों की याचिकाओं पर सुनवाई के क्रम पर फैसला करेगी। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मुद्दे का समाधान खो.जने के प्रयास जारी हैं और याचिक.ाओं को मई के पहले सप्ताह में सूचीबद्ध किया जा सकता है। झारखंड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि किसी भी स्तर पर समझौता किया जा सकता है और सुनवाई में देरी नहीं होनी चाहिए।

जम्मू-कश्मीर में विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए 45 परियोजनाएं चल रही हैं, 73 और की पहचान की गई है: उमर

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : जम्मू –कश्मीर सरकार ने गुरुवार को विधानसभा को सूचित किया कि केंद्र शासित प्रदेश में विरासत स्थलों के संरक्षण की योजना के तहत किलों और धार्मिक स्थलों सहित 45 परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

पुनरुद्धार, बहाली, संरक्षण और रखरखाव के लिए केंद्र शासित प्रदेश–स्तरीय योजना के चरण– प् के तहत 73 अति.रिक्त परियोजनाओं की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो संस्कृति विभाग के प्रभारी मंत्री भी हैं, ने यह बताया।

विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक फारूक अहमद शाह के एक अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में अब्दुल्ला ने उल्लेख किया कि केंद्र सरकार द्वारा मंजूर कोई भी विरासत संरक्षण परियोजना वर्तमान में जम्मू और कश्मीर में संस्कृति विभाग या पर्यटन विभाग द्वारा निष्पादित नहीं की जा रही है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि जेके सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश में वास्तुकला और विरासत के पुनरुद्धार, बहाली, संरक्षण और रखरखाव के लिए

एक योजना को मंजूरी दी है।

2019 और 2024 के बीच, पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के तहत 15 परियोजनाएं शुरू की गईं और 2022 में शुरू होने वाली सरकारी योजना के पहले चरण के तहत 33 परियोजनाओं पर काम प्रगति पर है। इसके अति.रिक्त, मुबारक मंडी हेरिटेज परिसर में सात परियोजनाएं नवीनीकरण और बहाली के अधीन हैं, मुख्यमंत्री ने कहा।

इसके अलावा, सरकारी योजना के चरण– प् के तहत विभिन्न किलों, स्मारकों, धार्मिक स्थलों और विरासत भवनों को कवर करने वाली 73 परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार

की गई है। अब्दुल्ला ने कहा कि पहले और दूसरे चरण को कवर करने के लिए ब्।च्म और न्ज–स्तरीय योजना के लिए 310.71 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। आज तक, कैपेक्स और परियोजनाओं के पहले चरण

के लिए 86.40 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

मुबारक मंडी, तवी नदी के किनारे पुराने चारदीवारी वाले शहर के मध्य में स्थित है। यह 1925 तक डोगरा राजवंश के शासकों का शाही निवास स्थान था, जब अंतिम महाराजा जम्मू के उत्तरी भाग में स्थित हरि निवास पैलेस में चले गए।

2005 में, मुबारक मंडी को एक संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था, और इसके संरक्षण, रखरखाव और जीर्णोद्धार के लिए परिसर को संभालने के लिए अगले वर्ष मुबारक मंडी जम्मू हेरिटेज सोसाइटी (डडश्रै) का गठन किया गया था।

इसके संरक्षण के लिए पहला विज़न डॉक्यूमेंट प्छज्।ब्र द्वारा 2008 में तैयार किया गया था, और बाद में एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया गया और 2019 में इसे मंजूरी दी गई।

परिसर को मुख्य रूप से छह क्षेत्रों में विभाजित किया गया हैरू सार्वजनिक क्षेत्र, ज्ञान केंद्र, व्याख्या और संग्रह गैलरी, जीवन शैली, अनुभवात्मक स्थान और शिल्प बाज़ार।

इस मास्टर प्लान के तहत, इस विरासत परिसर के भीतर विभिन्न उप–परियोजनाओं पर 144.15 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। कुछ उप–परियोजनाओं पर काम पूरा हो चुका है, जबकि अन्य पर काम प्रगति पर है। विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022 में शुरू की गई सरकारी योजना का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर की विरासत और स्थापत्य मूल्यों की मूल्य–आधारित बहाली, पुनरुद्धार, संरक्षण, रखरखाव और संवर्धन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय के माध्यम से विरासत स्थलों के लिए कानूनी और व्यवस्थित सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है।

केंद्र से पाकिस्तान से बातचीत करने को कहें : जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भाजपा सदस्यों से एनसी विधायक ने कहा

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

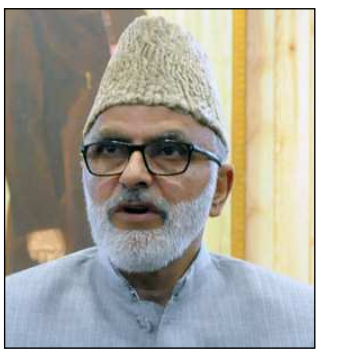

जम्मू : नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के विधायक अली मोहम्मद सागर ने बुधवार को पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की वकालत की और जम्मू–कश्मीर विधानसभा में भाजपा सदस्यों से पड़ोसी देश के साथ बातचीत करने के लिए नई दिल्ली पर दबाव डालने का आग्रह किया। एनसी विधायक ने देश भर में हो रही सांप्रदायिक झड़पों के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर भी कटाक्ष किया और कहा कि उनकी पार्टी महात्मा गांधी की विचारधारा का पालन करती है, न कि नाथूराम गोडसे की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा घोषित अनुदानों पर विधानसभा में बोलते हुए सागर ने कहा, ष्बातचीत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपने उल्लेख किया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की थी। (प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी ने पाकिस्तान का दौरा किया। हम हमेशा कहते हैं कि मुद्दों को हल करने का यही एकमात्र तरीका है।ष उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एनसी ने हमेशा शांति प्राप्त करने के मार्ग के रूप में बातचीत का समर्थन किया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों से कहा, ष्हमारे सम्मानित नेता डॉ. फारूक (अब्दुल्ला) साहब ने आपको (पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का) एक सुझाव दिया था और मैं आपसे ईमानदारी से इस रास्ते पर चलने की अपील करता हूं।ष भाजपा विधायकों से समर्थन मांगते हुए सागर ने कहा, ष्कृपया इस सुझाव (फारूक अब्दुल्ला के) को लेकर दिल्ली जाएं और उन्हें पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए कहें। ईश्वर की इच्छा से हमारा मुद्दा सुलझ जाएगा।ष सुलह का आह्वान करते हुए एनसी नेता ने देश में एक ही राजनीतिक विचारधारा थोपने के प्रयासों की आलोचना की। भाजपा पर धर्म और क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांटने का आरा.`प लगाते हुए सागर ने कहा, हम भाजपा से नफरत नहीं करते, लेकिन हम उसकी विचारधारा में विश्वास नहीं करते, जो लोगों को बांटती है।

बनिहाल निर्वाचन क्षेत्र में पीएमएवाई के तहत 4062 घर पूरे

रामबन में ग्रामीण विकास कार्यों पर 17,642.26 लाख रूपये खर्च किए गए–जावेद डार

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जावेद अहमद डार ने सज्जाद शाहीन द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए विधानसभा को बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत योजना की शुरुआत से अब तक 4,368 मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 4,062 मकान पूरे हो चुके हैं और सभी किश्तें वितरित की जा चुकी हैं।

उन्होंने आगे कहा कि पीएमएवाई के तहत योग्य लाभार्थियों के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि पात्रता मानदंडों में ढील दी गई है, जिसमें आय सीमा में वृद्धि और नई सुविधाओं को शामिल करना शामिल है।

मंत्री ने कहा "इससे यह योजना और अधिक लोगों के अनुकूल हो गई है। इसके अलावा, पीएमएवाई लाभार्थी के रूप में मान्यता के लिए, राशन कार्ड के अलावा, मनरेगा जॉब कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता संख्या और आधार कार्ड दस्तावेज भी स्वीकार किए जाते हैं।"

उन्होंने सदन को आगे बताया कि रामबन जिले में मनरेगा, सीडी पंचायत, पीआरआई, 14वें वित्त आयोग, एसबीएम, बैक टू विलेज, डीडीसी और बीडीसी अनुदान सहित विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले दो वर्षों के लिए विस्तृत कार्य–वार निधि आवंटन किया गया है। कार्यों का चयन स्थापित दिशानिर्देशों और योजना निर्माण मानदंडों के अनुसार किया गया है। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के तहत कुल 36,980 कार्य किए गए, जिनमें 28,967.44 लाख रुपए जारी किए गए तथा अब तक 17,642.26 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

सुरिंदर भगत के नेतृत्व में शहीद भगत अमरनाथ चौरिटेबल ट्रस्ट ने उपराज्यपाल से मुलाकात की

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : शहीद भगत अमरनाथ चौरिटेबल ट्रस्ट (पंजीकृत) के एक प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा, चंडीगढ़ के एससी मोर्चा के प्रभारी सुरिंदर भगत के नेतृत्व में उपराज्यपाल मंजो सिन्हा से मुलाकात की।

एडवोकेट अनुकूल भगत सामाजिक कार्यकर्ता, गुरमीत दत्ता मीडिया अध्यक्ष, रशपाल डिगरा भाजपा नेता, राजू शर्मा भाजपा नेता भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। श्रद्धा के प्रतीक के रूप में प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल को पुष्पगुच्छ भेंट किया तथा अनिल भारती जी द्वारा लिखित शहीद भगत अमरनाथ जी पर आधारित पुस्तक भेंट की।

सुरिंदर भगत ने पुस्तक के बारे में बताया कि किस प्रकार शहीद भगत अमरनाथ जी ने दलितों के उत्थान और जम्मू–कश्मीर में आरक्षण के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी।

सुरिंदर भगत ने अन्य लोगों के साथ मिलकर भगत अमरनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष की ओर से एलजी मनोज सिन्हा को एक पत्र सौंपा, जिसमें शहीद भगत अमरनाथ जी को "भारत रतन" पुरस्कार देने और उनकी जीवन उपलब्धियों और बलिदानों को आम जनता के कल्याण और उत्थान के लिए उनके बलिदान को देखते हुए नई शिक्षा नीति 2020 में शामिल करने की सिफारिश की गई।

सुरिंदर भगत ने कहा कि भगत अमरनाथ जी 1970 में जम्मू आए थे और 21 मई को सचिवालय नगर पालिका पार्क के सामने आमरण अनशन किया था। 1 जून 1970 को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने कहा कि भगत अमरनाथ जम्मू–कश्मीर के गुमनाम नायक हैं।

भगत अमरनाथ एक महान क्रांतिकारी समाजवादी और दलित अधिकारों के हिमायती थे; वे बेदाग छवि वाले राजनी. तिक व्यक्तित्व थे। उन्होंने कहा कि अमरनाथ जी ने सभी के कल्याण के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, ताकि वं. चतों जैसे एएलसी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, शारीरिक विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, महिला आरक्षण की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण का मार्ग खोला जा सके, जिसे जम्मू–कश्मीर में अनुच्छेद 370 के कारण लागू नहीं किया गया था।

विधायक रंधावा ने तवी क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया, युवा ऊर्जा को उत्पादक दिशा में लगाने पर जोर दिया

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : वरिष्ठ भाजपा नेता और विधायक बाहु, विक्रम रंधावा ने आज तवी क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया, जो क्षेत्र में युवा क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से एक नई पहल है।

आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ स्थापित इस अकादमी से महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों को खेल में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा और कोचिंग प्रदान करने की उम्मीद है।

उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, रंधावा ने युवाओं के बीच खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए अकादमी के मालिक सुरिंदर सिंह को बधाई दी। उन्होंने युवा ऊर्जा को उत्पादक दिशा में लगाने, उन्हें नशीली दवाओं के दुरुपयोग जैसे नकारात्मक प्रभावों से दूर रखने और अनुशासन, टीमवर्क और दृढ़ता को बढ़ावा देने में ऐसी पहलों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, युवाओं में नशे की बढ़ती समस्या एक गंभीर चिंता का विषय है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सुनीता विलियम्स को पत्र लिखकर भारत आने का निमंत्रण दिया

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को पत्र लिखकर भारत आने का निमंत्रण दिया है। विलियम्स नौ महीने तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने के बाद बुधवार को धरती पर लौटने वाली हैं। एक मार्च को लिखे गए इस पत्र को नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री माइक मैसिमिनो ने भेजा था। इसे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर साझा किया है।

मोदी ने पत्र में कहा, श्श्भले ही आप हजारों मील दूर हों, लेकिन आप हमारे दिल के करीब हैं। भारत के लोग आपके अच्छे स्वास्थ्य और आपके मिशन में सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, आपके लौटने के बाद हम आपको भारत में देखने के लिए उत्सुक हैं। भारत के लिए अपनी सबसे शानदार बेटियों में से एक की मेजबानी करना खुशी की बात होगी। मोदी ने 2016 में अमेरिका यात्रा के दौरान विलियम्स और उनके दिवंगत पिता दीपक पंड्या से हुई मुलाकात को याद किया।

उन्होंने कहा, ष्बातचीत के दौरान आपका नाम आया और हमने चर्चा की कि हमें आप पर और आपके काम पर कितना गर्व है। इस बातचीत के बाद, मैं खुद को आपको पत्र लिखने से नहीं रोक सका।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके पूर्ववर्ती जो बिडेन से अमेरिका की अपनी यात्राओं के दौरान मुलाकात के दौरान विलियम्स का हालचाल पूछा।

उन्होंने कहा कि 1.4 अरब भारतीयों ने हमेशा विलियम्स की उपलब्धियों पर बहुत गर्व किया है। ष्हाल के घटनाक्रमों ने एक बार फिर आपकी प्रेरणादायी दृढ़ता और दृढ़ता को प्रदर्शित किया है। मोदी ने कहा कि विलियम्स की मां बोनी पंड्या उनके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी और उन्हें यकीन है कि दीपकभाई का आशीर्वाद भी उनके साथ है।

प्रधानमंत्री ने विलियम्स के पति माइकल विलियम्स को भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजीं।

स्थानांतरण की मांग को लेकर जम्मू के नई बस्ती के दुकानदारों ने भूख हड़ताल शुरू की

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : जम्मू के नई बस्ती के लगभग 30 दुकानदारों ने उचित पुनर्वास की मांग करते हुए मंगलवार को भूख हड़ताल शुरू कर दी। इन दुकानदारों को जम्मू–पठानकोट राजमार्ग के सतवारी–बिक्रम–चौक खंड के विस्तार के लिए राजमार्ग प्राधिकरण से बेदखली का नोटिस मिला था। प्रशासन के साथ कई बैठकों के बाद दुकानदारों ने मंगलवार को भूख हड़ताल शुरू कर दी।

स्थानीय भाजपा नेताओं के नेतृत्व में दुकानदारों के परिवारों ने प्रशासन पर पिछले साल जुलाई में एलजी मनोज सिन्हा द्वारा प्रतिबद्धता के बावजूद जानबूझकर पुनर्वास में देरी करने का आरा. प लगाया।

"एलजी की प्रतिबद्धता को प्रशासन ने नजरअंदाज किया है। तीन महीने पहले अंतिम बैठक में, जेएमसी आयुक्त ने मौखिक आश्वासन दिया था कि सभी दुकानदारों को निर्माणाधीन चंद्रबाघा हॉल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यहां तक कि दुकानदारों के दस्तावेज भी मांगे गए, लेकिन बिना पुनर्वास के बेदखली नोटिस दिए गए, "भाजपा नेता और पूर्व पार्षद पवन ने कहा। उन्होंने अधिकारियों पर समय–समय पर लोगों के साथ किए गए अपने वादों को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया,

इससे पहले भाजपा विधायक शाम लाल शर्मा, सुरजीत सिंह सलाथिया, विक्रम रंधवा और डॉ. नरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और दुकानदारों के पुनर्वास का मुद्दा उठाया।

भाजपा ने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया और 39 दुक. ानदारों के उचित पुनर्वास की मांग की, जो कुंजवानी से सतवारी तक चल रहे फ्लाईओवर के निर्माण के कारण अपने व्यावसायिक परिसर खोने वाले हैं। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने भी आंदोलनकारी दुकानदारों को समर्थन दिया और कहा कि एलजी प्रशासन ने दुकानदारों से वादा किया था और भाजपा नेताओं द्वारा मिठाइयां बांटी गईं, लेकिन उस वादे का सम्मान नहीं किया गया और दुकानदारों को नोटिस दिए गए।

स्वामित्व, प्रकाशक एवम् मुद्रक संजीव कुमार मनमोत्रा द्वारा जन संपर्क प्रिंटिंग प्रेस सिधरा, जम्मू से मुद्रित करवाकर तथा अटल विहार हेरिटेज स्कूल सैनिक कॉलोनी जम्मू से प्रकाशित किया गया संपादक : संजीव कुमार मनमोत्रा, मोबाइल न : 9419141189, ईमेल : editorjammuladakhvision1@gmail.com